

‘संसद का तीन दिन का विशेष सत्र, एक “चुनावी सत्र” है’

कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा इस तीन दिवसीय सत्र में महिला आरक्षण विधेयक व लोकसभा की सीटों के परिसीमन के आड़ में सीटों की संख्या बढ़ाने का विधेयक “बुलडोज़” करना चाहती है

रेणु मित्तल-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। कांग्रेस ने आज कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को होने वाला संसद का विशेष सत्र आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। पार्टी ने कहा कि इसका उद्देश्य इस महीने के अंत में होने वाले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों को प्रभावित करना है।

कांग्रेस ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन में किसी भी जल्दबाजी के प्रति चेतावनी दी और कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और सरकार को इसे सावधानी से संभालना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया संशोधन तमिलनाडु और केरल जैसे कई राज्यों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है।

पार्टी महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि सरकार महिलाओं के आरक्षण विधेयक से

कांग्रेस की पुरानी “थ्योरी” है कि परिसीमन बढ़ा संवेदनशील मुद्दा है और इससे दक्षिण भारत के राज्यों, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का भारी राजनीतिक नुकसान होगा।

कांग्रेस का यह भी आरोप है कि संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, दो-तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष खड्गे को पत्र लिखकर प्रस्तावित कर चुके हैं कि सरकार कांग्रेस से विशेष सत्र के बारे में विचार करना चाहती है, पर, हर बार खड्गे, एक ही जवाब दे रहे हैं कि अलग से कांग्रेस से बातचीत करने के बजाए एक सर्वदलीय बैठक आहूत करें, जिसमें पूरे विपक्ष को इन मुद्दों पर अपनी-अपनी सोच सामने रखने का मौका मिले।

संबंधित संशोधनों पर कांग्रेस के साथ चर्चा करना चाहती है।

जयराम रमेश ने कहा कि खड्गे ने रिजिजू को जवाब दिया और सुझाव दिया कि अलग-अलग पार्टियों से मिलने के बजाय सरकार 29 अप्रैल के बाद सभी पार्टियों की बैठक बुलाए, जब पांच राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि 24 मार्च को सभी विपक्षी दलों ने सरकार से इसी तरह की बैठक 29 अप्रैल के बाद बुलाने का

अनुरोध किया था, क्योंकि तब तक अधिकांश पार्टियां विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगी।

रमेश ने बताया कि रिजिजू ने 26 मार्च को फिर से खड्गे को लिखा और कहा कि सरकार प्रस्तावित संविधान संशोधन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के साथ चर्चा करना चाहती है। खड्गे ने पुनः जवाब दिया और कहा कि सरकार को अलग बैठक करने के बजाय सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने मनमाने तरीके से 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर होगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक को 2023 में पास किया गया था और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की मांग की थी। रमेश ने कहा, “जैसे डबल इंजन सरकार के दावे हैं, भाजपा अब महिलाओं के आरक्षण से दोगुना लाभ लेना चाहती है।”

जयराम रमेश ने कहा कि सरकार लगभग 30 महीने बाद जागी है और 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सरकार 15 दिन और इंतजार कर विपक्षी दलों से परामर्श कर सकती थी और उसके बाद सत्र बुला सकती थी। उन्होंने सरकार की समयसीमा पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के आदेश में संशोधन किया

जयपुर, 3 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की 5 और 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को शामिल करने के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों के दायरे को सीमित करते हुए, सिर्फ याचिकाकर्ता

अब वर्ष 2024 के केवल उन अभ्यर्थियों को 2025 की परीक्षा में शामिल किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हैं।

को ही परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश सुर्जमल मीणा की ओर से दायर याचिका में आरोपीएससी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और परीक्षा तय समय पर ही ली जाएगी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश अदालत नहीं आने वाले अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि भर्ती परीक्षा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ईरान वॉर से हट गए तो क्या होगा, चिंतित हैं अमेरिका के मित्र राष्ट्र

ये देश चाहते हैं, पहले होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए

श्रीनंद झा-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। अमेरिका के सहयोगी इस संभावना को लेकर चिंतित हैं कि यदि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से मुक्त व्यापारिक आवाजाही सुनिश्चित किए बिना ईरान युद्ध से बाहर निकल गया तो क्या होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बार-बार नाटो देशों की इस बात के लिए आलोचना की है कि वे ईरान के नियंत्रण से जलमार्गों को मुक्त कराने के लिए अपनी सेनाएं तैनात करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ईरान संघर्ष में अमेरिका के लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं।

यूरोप को 40 यूरोपीय, एशियाई और मध्य-पूर्वी देशों के अधिकारियों के साथ-साथ कैनडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रतिनिधियों ने एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के दो उद्देश्य थे: पहला, अमेरिका पर दबाव बनाना कि वह ईरान के साथ युद्धविराम वार्ता में होर्मुज का समाधान शामिल करे। दूसरा, उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करना, क्योंकि ट्रंप के सहयोगी संभावना

अमेरिका के मित्र राष्ट्रों व एशिया के कुछ देशों ने इस बारे में एक मीटिंग कर दो मुद्दे तय किए।

पहला मुद्दा है कि अमेरिका पर दबाव डाला जाए कि वह ईरान के साथ सीजफायर वार्ता में होर्मुज से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बात करे। दूसरा मुद्दा है कि सुरक्षित आवाजाही के लिए सभी उपलब्ध कूटनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल किया जाए।

पर, ट्रंप नाटो के अपने सहयोगी देशों से काफी नाराज हैं, खासकर, इसलिए क्योंकि ईरान वॉर के दौरान इन देशों ने अमेरिका का सहयोग करने से साफ इन्कार कर दिया है।

कम मानी जा रही थी। इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं था, क्योंकि ट्रंप पहले ही यह कह चुके थे कि “जलमार्गों की सुरक्षा करना अमेरिका का काम नहीं है।” उन्होंने हाल ही में सहयोगियों से कहा था, “जाकर अपना खुद का तेल लाओ।”

इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन की विदेश सचिव डेवेट कूपर ने की। इसका उद्देश्य था, “सभी संभावित कूटनीतिक और राजनीतिक उपायों का

आकलन करना, ताकि नौवहन की स्वतंत्रता बहाल की जा सके, फंसे हुए जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही फिर से शुरू हो सके।”

गठबंधन देशों के सैन्य योजनाकारों ने यह भी तय किया है कि वे अगले सप्ताह बैठक करेंगे, जिसमें यह चर्चा होगी कि लड़ाई समाप्त होने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नेशनल और स्टेट हाईवे सहित जयपुर को जोड़ने वाले मार्गों से अतिक्रमण हटाएं’

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि “जहां जेडीए अधिनियम की धारा 72 के नोटिस जारी किए गए हैं, उन मामलों में कोई भी सिविल न्यायालय या जेडीए ट्रिब्यूनल हस्तक्षेप नहीं करेगा”

यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 3 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डबलपैमेंट अथॉरिटी (जेडीए) की अतिक्रमण विंग को आदेश दिए हैं कि वह नेशनल और स्टेट हाईवे पर हुए अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए कदम उठाए, साथ ही जयपुर शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों व आसपास की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। कार्यवाहक न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे को लेकर विजय कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई

हाईकोर्ट ने यह आदेश सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर विजय कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिए।

उधर जेडीए प्रशासन ने सिरसी रोड पर खातीपुरा तिराहे से झाड़खंड मोड़ तक अतिक्रमण हटाने को लेकर 6 सप्ताह का समय हाईकोर्ट से मांगा है।

करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया है। ऐसे में जिन मामलों में जेडीए ने मास्टर प्लान में आने वाली भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए

जेडीए अधिनियम की धारा 72 के नोटिस जारी किए हैं, उन मामलों में कोई भी सिविल न्यायालय या जेडीए ट्रिब्यूनल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके साथ ही, अदालत ने जेडीए को कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके

नई दिल्ली, 03 अप्रैल। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केन्द्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश था। अफगान-ताजिकिस्तान बॉर्डर पर भी 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केन्द्र जमीन की सतह से 150 किलोमीटर अंदर था। भूकंप के झटके

भूकंप का केन्द्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 नापी गई।

चार देशों- भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में महसूस किए गए।

किसी तरह के जान-माल के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में रात 9: 46 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। घबराए लोग घरों से बाहर आ गए।

अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान एफ-15 मार गिराया ईरान ने

इस विमान में दो पायलट होते हैं, पायलट को दूढ़ने के लिए अमेरिका ने भारी “सर्च और रेस्क्यू” ऑपरेशन शुरू किया

अंजन राय--

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। अमेरिका को एक नया झटका देते हुए ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में एक-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। विमान के पायलट की तलाश के लिए खोज अभियान शुरू किया गया है।

अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों ने हाल ही में विमान के नुकसान की पुष्टि की है। अमेरिकी एजेंसियां कथित तौर पर पायलट और चालक दल की तलाश के लिए व्यापक खोज अभियान चला रही हैं।

यह अमेरिका के लिए एक और झटका है, क्योंकि वह ईरानी हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करता रहा है, जिसमें ईरान की एंटी-एयरक्राफ्ट क्षमताओं की निगरानी भी शामिल है। अमेरिकी विमानों को आमतौर पर अपने मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम से अत्यंत

इस विमान को मार गिराने से अमेरिका व इजरायल के लिए भारी अटपटी स्थिति पैदा की है, क्योंकि जिस स्थान पर ईरान ने इस विमान को मार गिराया है, उस स्थान को अमेरिका व इजरायल दोनों पूर्णतया अपना आधिपत्य में होने का दावा करते रहे हैं।

दूसरी ओर ईरान ने घोषणा की है कि वह अमेरिका के इन्फास्ट्रक्चर लिंक्स जैसे महत्वपूर्ण सड़क व पुल को अपना टारगेट बनायेगा, बमबारी के लिए।

इससे काफी दहशत फैली है, खाड़ी देशों में और लड़ाई सिटमने के बजाय और व्यापक होती जा रही है।

सटीक जानकारी और राक्षसक खुफिया सहायता मिलती है, जिससे वे दुश्मन के हमलों से बच सकें।

एफ-15 विमान में दो पायलट होते हैं, इसलिए गिराए गए विमान में भी दो पायलट सवार थे। अमेरिका ने तुरंत

खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है और कई विमान पहले से ही उड़ान पर रहे हैं। बचाव दल में आमतौर पर फिक्स्ट-विंग विमान और हेलीकॉप्टर, दोनों शामिल होते हैं। कुछ ईरानी समाचार एजेंसियों ने

दावा किया है कि उन्होंने बचाव अभियान के हिस्से के रूप में अमेरिका के बड़े हेलीकॉप्टरों को देखा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ईरानी हमले के बाद इन टीमों को पीछे हटना पड़ा।

अमेरिकी पायलटों को ऐसी परिस्थितियों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें बच निकलना और गिरफ्तारी से बचाव शामिल है। इसके अलावा, उनके पास ऐसे सिमलिंग उपकरण होते हैं, जो उनकी लोकेशन अमेरिकी बलों को बता सकते हैं। हालांकि ये बचाव अभियान स्वयं बचाव दल और उनके विमानों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं।

ईरान ने अब तक पायलट और चालक दल के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, सिवाय इसके कि उनके बारे में जानकारी देने पर भारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

माल्दा में जजों के घेराव की जाँच एनआईए करेगी

जाल खंबाता-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव की जाँच एनआईए (राष्ट्रीय जाँच एजेंसी) को सौंप दी।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को “सबसे अधिक घुचीकृत राज्य” बताया

चुनाव आयोग ने 2 अप्रैल को इस संबंध में एनआईए को चिट्ठी लिखी है।

हुए राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की, जब मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों, जो एसआईआर कार्य में लगे थे, प्रदर्शनकारियों द्वारा बंधक बनाए गए। कोर्ट ने सीबीआई या एनआईए द्वारा इस घटना की जाँच करायें जाने के निर्देश दिये। 2 अप्रैल को लिखे एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने एनआईए को सुप्रीम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल में भाजपा को यह साबित करना भारी पड़ रहा है कि वह मछली विरोधी नहीं है

तृणमूल ने चुनाव प्रचार को भ्रष्टाचार, रोजगार व सत्ता विरोध से हटाकर “मछली खाने” के मुद्दे पर केन्द्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है

जाल खंबाता-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के चुनावी जल में मछली अब सिर्फ थाली तक सीमित नहीं रही; यह राजनीति का केन्द्र बन गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) बंगाली गौरव को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा इस बात से बचने के लिए संघर्ष कर रही है कि वह “माछे भाते बंगाली” कहावत के गलत साइड पर न आ जाए। विशालकाय मछली ‘कतला’ से लेकर ‘इलीश’, पाबदा और चिंगरी को राजनीतिक भाषणों में प्रमुख स्थान मिल रहा है, और मछली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एक अप्रत्याशित, लेकिन प्रभावशाली प्रतीक बन गई है।

भोजन की आदतें अब पहचान, संस्कृति और “असली” बंगाली का प्रतिनिधित्व करने वाले मुद्दों पर तीव्र संघर्ष में बदल गई है।

पुरानी बंगाली कहावत ‘माछे भाते बंगाली’, जिसका अर्थ है कि एक बंगाली की पहचान मछली और चावल के सेवन से होती है, इस चुनाव में विभिन्न दलों के लिए असली (डि फ्रैक्टो) नारा बन गई है।

टीएमसी ने इस भावना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है, यह तर्क देते हुए कि भाजपा, जिसे टीएमसी हिंदी भाषियों और उत्तर भारत की शाकाहार को प्रोत्साहित करने वाली राजनीति से जोड़ती है, पश्चिम बंगाल के लिए सांस्कृतिक रूप से परायी तथा

ममता बनर्जी अपनी रैलियों में जोर शोर से दावे कर रही हैं कि भाजपा बाहरी पार्टी है, यह बंगाल में मछली, मीट व अंडे पर रोक लगा देगी, उन्होंने नारा दिया है “माछे भाते बंगाली” अर्थात् बंगाली की पहचान मछली, चावल खाने से होती है।

तृणमूल के सोशल मीडिया एकाउंट्स पर भी मछली के व्यंजनों की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। यही नहीं शाह ने जब बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए 15 दिन रुकने की बात कही तो उनसे मछली के व्यंजनों का तुल्फ उठाने का आग्रह भी किया गया।

भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तृणमूल को मात देने के लिए। पार्टी ने सफाई दी है कि वह मछली आदि के सेवन पर रोक नहीं लगाएगी। उन्होंने तृणमूल पर चुनाव प्रचार को भटकाने और खाने के मैनु कार्ड तक लाने का आरोप लगाया।

विदेशी है और यदि वह सत्ता में आती है, तो मछली, मांस और अंडे पर प्रतिबंध लगा सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली

में इस हमले को तेज करते हुए कहा, “वे आपको मछली नहीं खाने देंगे। आप मीट नहीं खा सकते, अंडे नहीं खा सकते, बंगाली में बात नहीं कर सकते।

अगर आप करेंगे, तो वे आपको बांग्लादेशी कहेंगे।” इस तरह से बनर्जी ने भोजन, भाषा और बंगाली पहचान को एक राजनीतिक मुद्दे से जोड़ा।

इस आरोप से टीएमसी अपने अभियान को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता विरोध से हटाकर, उस क्षेत्र में ले गई है, जहाँ वह अधिक सहज महसूस करती है, यानी “बंगाली उपराष्ट्रियता।” मछली अब केवल भोजन नहीं, बल्कि बंगाली गौरव का प्रतीक बन गई है। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स ने उस समय इलीश भापा, पाबदा झाल, चिंगरी मलाई करी और कोषा मंगशो जैसे व्यंजनों की तस्वीरें पोस्ट कीं, जब केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए 15 दिन बिताएंगे।

टीएमसी के एक पोस्ट में शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा, “पश्चिम बंगाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मालदा कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

कोलकाता, 03 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की मालदा हिंसा में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान और पूरा मामला एनआईए को रेफर होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मालदा घटना पर

पुलिस ने बताया कि आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को एनआईए को सौंप दिया गया है।

उत्तरी बंगाल के एडीजी के. जयरामन के अनुसार अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसा में 19 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि हिंसा मड़काने वाले मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को अरेस्ट किया गया है। वह अभी बागडोगरा में हिरासत रखा गया है। एडीजी के. जयरामन ने बताया कि उसे यहाँ लाया जा रहा है। आगे एनआईए इस मामले की जांच अपने हाथ में लेगी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

निरन्तर बदलने की इच्छा रखना एक ताकत होती है, चाहे इसकी वजह से कंपनी का एक बड़ा हिस्सा कुछ देर के लिए पूरी तरह से अव्यवस्थित क्यों ना हो जाए। -जैक वेल्स

नकली उत्पाद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

आर्थिक सहयोग और विकास संघटन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, नकली वस्तुओं का व्यापार विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 500 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व उत्पन्न करता है। यह समस्या केवल वित्तीय पहलू तक ही सीमित नहीं है। नकली उत्पाद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। मिलावटी दवाएं, विषैले पदार्थों से युक्त सौंदर्य प्रसाधन, सुरक्षा प्रमाणन के बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घटिया गुणवत्ता वाले वाहन पुर्जे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो वास्तविक खतरों को दर्शाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विलासिता के सामान का बाजार लगातार परिष्कृत नकली उत्पादों से जूझ रहा है। लुईविटन, गुच्ची, नाइकी और एप्पल जैसे ब्रांड इसके प्रमुख निशाने पर हैं और बाजार में लगातार अधिक विश्वसनीय नकली उत्पाद पहुंच रहे हैं। दवा क्षेत्र को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नकली दवाओं में सक्रिय तत्व की कमी हो सकती है या उनमें हानिकारक पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नकली चार्जर, हेडफोन, स्मार्टवॉच और तकनीकी सहायक उपकरण न केवल कम टिकाऊ होते हैं, बल्कि पर्याप्त सुरक्षा मानकों के अभाव के कारण आग और बिजली के शटके जैसे दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं।

देशभर में प्रतिदिन नकली और घटिया उत्पादों का न केवल भंडाफोड हो रहा है अपितु आये दिन लाखों करोड़ों का नकली सामान बरामद हो रहा है। लोगों को धरपकड़ भी लगातार हो रही है मगर इस नकली उत्पादों का आज तक प्रभावी रोक नहीं लग पायी है। बाजार में नकली उत्पादों की बिक्री से स्थानीय उत्पादकों के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार नकली सामान देश के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। इससे लाखों वैध रोजगार खत्म होने का खतरा है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। उद्योग मंडल ने कहा कि उद्योग को केवल सात क्षेत्र वाहन कल-पुर्जे, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कंप्यूटर हार्डवेयर, रोजमर्रा के उपयोग के डिब्बाबंद दवा तथा व्यक्तिगत उपयोग वाले सामान, सिगरेट तथा मोबाइल फोन से जुड़े उद्योग को भारी नुकसान होने का अनुमान है।

नकली सामान की समस्या से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है। एक अनुमान के मुताबिक, वैश्विक बाजार में नकली सामान की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत तक है। भारत में हालात ज्यादा चिंताजनक हैं। देश में नकली उत्पादों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, यहां 30 प्रतिशत तक नकली माल बाजार में मिलता है। क्रिसिल मार्केट इंटरलिजेंस एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में नकली उत्पादों का मार्केट बहुत तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। देश के 9 प्रमुख शहरों में किये गए एक सर्वे के अनुसार 2025 में 35 प्रतिशत शहरी उपभोक्ताओं ने नकली उत्पाद खरीदने की बात स्वीकार की है। इसके अलावा 89 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपने जीवन में कम से कम एक बार नकली उत्पादों के शिकार कर चुके हैं। कपड़े का बाजार नकली उत्पादों का प्रमुख बाजार है।

दवाओं के मामले में भी चिंताजनक स्थिति है। नकली सामानों से घिरी इस दुनिया में, थोड़ा-थोड़ा से खुद को बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। ऑनलाइन खरीदारी के प्रति सतर्क रहना अपना कर, उपभोक्ता जालसाजों से होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। विक्रेताओं पर शोध करना, उत्पाद समीक्षाओं की बारीकी से जांच करना और प्रामाणिकता की पुष्टि करना जैसी सरल रणनीतियाँ नकली सामानों की बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करती हैं।

नकली सामान केवल लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं है। घर की रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाले जौरे से लेकर खाना पकाने के तेल और बच्चों की देखभाल के सामान से लेकर दवाओं तक नकली सामानों की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। खाने-पीने की चीजें, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हाउसहोल्ड केयर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट और स्टेशनरी आदि अपैरल यानी फैशन के कपड़ों और एप्लीकेशनल यानी बीज और खाद में सबसे ज्यादा नकली माल बाजार में मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे परिया में नकली सामान का बाजार 20 से 25 प्रतिशत तक है। नकली सामान खुले बाजार बिक रहा है। मिलावटी या नकली खाने-पीने की चीजें, जीवन रक्षक दवाएं, कृषि उत्पाद, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और फूडसफ्लिमेट बेच कर जिंदगी से खेला जा रहा है। नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, गैजेट्स और फैशन की चीजों से कंज्यूमर ठगे जा रहे हैं। नकली सामानों की घुसपैठ और तस्करी पर रोक ना लगने से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। केवल पांच प्रमुख सेक्टरों में ही नकली सामानों और स्मगलिंग की वजह से सरकार को सालाना 8 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है।

इन सेक्टरों में, टेक्सटाइल एंड अपैरल, अल्कोहल और टोबैको शामिल हैं। नकली सामानों का ये अवैध ट्रेड सबसे ज्यादा सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नकली सामान एक प्रमुख मुद्दा है, जिससे उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकारों को बहुत ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसमें नकली फैशन उत्पादों से लेकर नकली दवाइयों तक शामिल हो सकते हैं, जो उपभोक्ता की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्रांड के परोसे को खत्म कर सकते हैं और भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तव में, के अनुसार कॉर्सर्व अनुमान वर्ष 3.3 में वैश्विक व्यापार में नकली वस्तुओं की हिस्सेदारी 2023 प्रतिशत होगी और वर्ष 5 तक अंदाजित बढ़कर 2030 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। यह एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति है जो समस्या के पैमाने और तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

-अतिथि संपादक, बाल मुकुन्द ओझा, वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

राशिफल शनिवार 4 अप्रैल, 2026



पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शनिवार, विक्रम संवत् 2083, स्वाती नक्षत्र रात्रि 9:36 तक, हर्षण योग दिन 2:17 तक, गर करण दिन 10:09 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा। प्रस्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मीन, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 9:36 तक है। भद्रा रात्रि 11:04 से आरम्भ होगा। आज हस्तर सेटर डे है। श्रेष्ठ चौघड़िया, शुभ 7:51 से 9:29 तक, चर 12:30 से 2:03 तक, लाभ-अमृत 2:03 से 5:08 तक। राहुकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:19, सूर्यास्त 6:41

मेष	सिंह	धनु
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।	परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन/संदेश प्राप्त होंगे।	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़त से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में सफल रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।
वृष	कन्या	मकर
विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	विवाहित मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।	व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में सार्थक सफलता मिल सकती है। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।
मिथुन	तुला	कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरिपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्यों में योजनानुसार बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन/संदेश प्राप्त होंगे।
कर्क	वृश्चिक	मीन
परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। समग्र अनावश्यक खर्चा होगा। मन में असंतोष और धय बना रहेगा।	चन्द्रमा अग्रम भाव में शुभ नहीं है। आश्विन और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में तुलना बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

जमीन बेचकर कब तक बंटेंगी पेंशन? नीतिगत भेदभाव ने विश्वविद्यालयों को कंगाल किया



डॉ. पी. सी. कंठालिया

राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह स्थिति केवल विडंबना नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। जिन वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने प्रदेश की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, वही आज अपने बुढ़ापे में पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, और कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है।

इसके बावजूद कृषि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन समस्या वर्षों से उपेक्षित है। पिछले पाँच दशकों में राजस्थान ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। 1960 के दशक में जहाँ गेहूँ का उत्पादन लगभग 20 लाख टन था, वहीं आज यह 120 लाख टन से अधिक हो चुका है। सस्ती उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान

पर है, जबकि धनिया और ग्वार जैसी फसलों में भी राज्य अग्रणी है। इन उपलब्धियों के पीछे कृषि विश्वविद्यालयों की वैज्ञानिक शोध प्रणाली और विस्तार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन आज यही संस्थान अपने ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन देने में असमर्थ दिखाई देते हैं।

स्थिति को गंभीरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपने पेंशन दायित्वों के निर्वहन के लिए अपनी बहुमूल्य अनुसंधान भूमि का एक हिस्सा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। नगर विकास प्रयास को भूमि हस्तांतरित कर लगभग 190 करोड़ रुपये जुटाए गए, लेकिन यह राशि भी स्थायी समाधान साबित नहीं हुई। हर महीने करोड़ों रुपये को पेंशन देनदारी के सामने संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में पेंशनरों की लगभग 22 महीनों की पेंशन बकाया बताई जाती है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद। स्थिति और भी गंभीर है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत की स्वीकृत दर के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति केवल वित्तीय संकट ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का भी संकेत

है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान में देरी, सतत वेतनमान के एरियर का लंबित रहना, स्वीकृत दर के अनुसार महंगाई भत्ता न मिलना, 70 एवं 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ न मिलना तथा कम्प्यूटेड पेंशन पर रोक जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कृषि विश्वविद्यालयों की संरचना ही ऐसी है कि उनके पास आय के सीमित स्रोत होते हैं।

पारंपरिक विश्वविद्यालयों की तरह उन्हें परीक्षा शुल्क, संबद्धता शुल्क या बड़े पैमाने पर शिक्षण शुल्क से आय प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए, बीकानेर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में लगभग 500 छात्र हैं, जबकि वहाँ 500 से अधिक कर्मचारी और लगभग 1200 पेंशनर हैं। पेंशन पर वार्षिक व्यय लगभग 60 करोड़ रुपये है, जिसे केवल शुल्क आय से वहन करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उदयपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में ही 1300 से अधिक पेंशनर हैं, जिन पर प्रति माह लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपये का व्यय आता है। इस प्रकार वार्षिक पेंशन भार 70 से 75 करोड़ रुपये तक पहुँच जाता है। यदि पूरे राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को मिलाकर देखा जाए, तो 3000 से अधिक पेंशनरों पर प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

राजस्थान सरकार का 2026-27 का बजट लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये है। इस दृष्टि से कृषि विश्वविद्यालयों के पेंशनरों पर आने

वाला 200 करोड़ रुपये का भार कुल बजट का मात्र 0.06 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 28,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ऐसे में 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं के निर्धारण की है।

समस्या की जड़ नीतिगत असमानता और वित्तीय ढांचे की खामियों में निहित है। जहाँ अन्य सरकारी निकायों के कर्मचारियों की पेंशन को जिम्मेदारी राज्य सरकार ने अपने कंधर ले ली, वहीं विश्वविद्यालय कर्मचारियों को उनके सीमित पेंशन फंड के परोसे छोड़ दिया गया, जो 2010 के आसपास लगभग समाप्त हो चुका था। अन्य राज्यों-जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश-में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। इसके विपरीत राजस्थान में यह जिम्मेदारी संस्थानों पर डाल दी गई है, जिनकी वित्तीय क्षमता अत्यंत सीमित है। यह अंतर स्पष्ट करता है कि समाधान संभव है, यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो।

पेंशन कोई अग्रह नहीं, बल्कि कर्मचारियों का अर्जित अधिकार है। यह उनके 30-35 वर्षों की सेवा और योगदान का प्रतिफल है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि उन्नति और शिक्षा के लिए समर्पित किया, उन्हें जीवन के

अंतिम चरण में आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़े, यह न केवल अन्याय है बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी प्रश्नचिह्न है। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को केवल वित्तीय बोझ के रूप में न देखकर सामाजिक और नैतिक दायित्व के रूप में देखे। विश्वविद्यालय कर्मचारियों को पेंशन व्यवस्था को राज्य कोष से सुनिश्चित किया जाए तथा विश्वविद्यालय पेंशन नियम, 1990 में आवश्यक संशोधन कर इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान बनाया जाए। किसी भी संस्थान की साख उसकी इमारतों या बजट से नहीं, बल्कि उन लोगों के सम्मान से बनती है जिन्होंने उसे खड़ा किया। यदि वही लोग अपने जीवन के अंतिम चरण में उपेक्षा का शिकार हों, तो यह केवल संस्थान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक पराजय है।

अंततः यह प्रश्न केवल पेंशन का नहीं, बल्कि उस दृष्टिकोण का है कि जिससे हम अपने ज्ञान निर्माताओं और कृषि विकास के आधार स्तंभों को देखते हैं। राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा कि वह अपने वैज्ञानिकों को असुरक्षा में छोड़ना चाहती है या उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा कर एक जिम्मेदार शासन का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है।

-डॉ. पी. सी. कंठालिया, पूर्व प्रोफेसर एवं उपाध्यक्ष महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि.वि. पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी, उदयपुर

शिक्षा या सौदा? बाजारीकरण और लुप्त होती गुरु-शिष्य परम्परा



प्रोफेसर अशोक कुमार

नारायण मूर्ति ने एक बार कहा था कि "संस्थान ईंट और गारे से नहीं, बल्कि वहां के मूल्यों से बनती हैं।" लेकिन आज के आधुनिक भारत में, महानगरीय शहरों के वातानुकूलित क्लासरूम में, ये मूल्य धीरे-धीरे फीस की रसोई के नीचे दबते जा रहे हैं। जब एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, तो उसके सामने बैठे छात्र अब जिज्ञासु शिष्य कम और जागरूक ग्राहक अधिक नज़र आते हैं। यह बदलाव रॉटों-रॉटों नहीं आया, बल्कि इसके पीछे सामाजिक ताने-बाने का वह बिखराव है जहाँ गुरु को एक सर्विस प्रदाता और शिक्षा को एक खरीदे जा सकने वाले उत्पाद के रूप में देखा जाने लगा है।

जब एक अभिभावक शिक्षक यह कहता है कि "मेरे बच्चे की फीस से आपका घर चलता है," तो वह केवल एक शिक्षक का अपमान नहीं करता, बल्कि वह अपने ही बच्चे के भविष्य से उस नैतिक अधिभार को छीन लेता है जो उसे एक बेहतर इंसान बना सकता था। शिक्षा का बाजारीकरण और छात्रों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला

हुमिलिएशन (अपमान) का कार्ड आज के शिक्षकों को एक ऐसे रक्षालतक मोड़ में ले आया है, जहाँ वे विरिधियों से ब्यादा खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह केवल एक शिक्षक की पीड़ा नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकट का आईना है, जिसे प्रति आज नहीं सुधारा गया, तो हम डिग्री धारक रॉबोट्स तो पैदा कर लेंगे, लेकिन चरित्रवान नागरिक छो देंगे।

यह विषय आज के शैक्षणिक परिदृश्य की एक ऐसी दुखती रग है, जिस पर चर्चा करना अनिवार्य हो गया है। नोएडा के उस शिक्षक का अनुभव केवल एक व्यक्ति की व्यथा नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के नैतिक पतन का संकेत है। जब शिक्षा को ज्ञान के बजाय उत्पाद और छात्र को शिष्य के बजाय ग्राहक मान लिया जाता है, तो गुरु-शिष्य परंपरा की नींव हिलने लगती है। आइए, इस जटिल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ताने-बाने को विस्तार से समझते हैं। अभिभावकों का यह तर्क कि "शिक्षकों को वेतन हमारे बच्चों की फीस से मिलता है," शिक्षा के मॉडल को एक व्यावसायिक शोरूम में बदल देता है। यह सोच न केवल संकुचित है, बल्कि धातक भी है।

उपभोक्तावादी मानसिकता जब अभिभावक शिक्षा को एक खरीदी गई सेवा मानते हैं, तो वे अनजाने में अपने बच्चे को यह सिखा रहे होते हैं कि पैसा सम्मान से ऊपर है। यदि बच्चा घर पर यह सुनता है कि "हम शिक्षक को पैसे देते हैं," तो वह कक्षा में शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में देखता है। मनोविज्ञान कहता है

कि बच्चा उस व्यक्ति से कभी नहीं सीख सकता जिसका वह सम्मान नहीं करता।

2. **सूक्ष्मात्मक अतिशयोक्ति** आज के दौर में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का चलन बढ़ा है। अभिभावक अपने बच्चे की हर गलती का बचाव करते हैं। जब शिक्षक बच्चे को सुधारने के लिए टोकता है, तो अभिभावक इसे बच्चे का अपमान समझकर शुकल पहुँच जाते हैं। इससे बच्चे के मन में यह धारणा बैठ जाती है कि वह अजेय है और कोई उसे उसकी गलती का अहसास नहीं करा सकता। अक्सर छात्र यह शिकायत करते हैं कि सवाल पूछने पर या गलती करने पर उन्हें हुमिलिएट (अपमानित) किया गया। यहाँ हमें बारीक अंतर समझने की जरूरत है।

अनुशासन बनाम अपमान: एक शिक्षक का काम केवल तथ्य पढ़ाना नहीं, बल्कि व्यवहार सुधारना भी है। यदि सुधार की प्रक्रिया को छात्र अपमान का नाम देने लगें, तो शिक्षक सुरक्षित खेलने लगता है। वह पढ़ाकर निकल जाता है, छात्र के चरित्र निर्माण से खुद को अलग कर लेता है।

सहनशीलता में कमी: आधुनिक मनोवैज्ञानिक परिवेश में छात्रों की इमोशनल रेजिलिएंस (भावनात्मक लचीलापन) कम हुई है। वे हल्की सी आलोचना भी सहन नहीं कर पाते। इसे स्नोफ्लेक जनरेशन का प्रभाव भी कहा जाता है, जहाँ बच्चा खुद को बहुत नाजुक समझने लगता है।

आज का शिक्षक एक ऐसी दोधारी तलवार पर चला रहा है जहाँ एक तरफ उसे पाठ्यक्रम पूरा करना है और दूसरी तरफ अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा बचानी है। ऐसे में शिक्षक क्या करे?

1. सत्ता से नहीं, व्यक्तिव

से प्रभाव अब वह समय चला गया जब शिक्षक डंडे के जोर पर सम्मान पाते थे। आज के शिक्षक को इमोशनल इंटेलिजेंस (इआइ) का सहारा लेना होगा। छात्र के साथ एक कनेक्ट स्थापित करना होगा। जब छात्र को लगता है कि शिक्षक वास्तव में उसका भला चाहता है, तो वह टोकने पर बुरा नहीं मानता।

2. **स्पष्ट संवाद की नीति** शिक्षक को कक्षा के नियम पहले दिन ही स्पष्ट करने चाहिए। अनुशासन को सजा के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के माहौल के रूप में देखा करना चाहिए। सवाल पूछने पर यदि बच्चा झिझकता है, तो शिक्षक को एक सुरक्षित वातावरण बनाना होगा जहाँ गलत जवाब पर कोई हंसे नहीं। शिक्षा केवल स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। एक बच्चे का व्यक्तित्व त्रिकोणीय सहयोग पर टिका है: शिक्षक, छात्र और अभिभावक। अभिभावक का दायित्व प्रभाव, शिक्षक का सम्मान करना, बच्चा घर के माहौल से ही दूसरों का आदर करना सीखता है। गलती को स्वीकारना। बच्चे को सिखाएं कि गलती करना बुरा नहीं है, उसे सुधारना जरूरी है। स्कूल को पार्टनर मानना। स्कूल को सर्विस प्रोवाइडर के बजाय पार्टनर समझे। फीस और सम्मान को अलग रखना। पैसा शिक्षा की सुविधा के लिए है, गुरु की गरिमा खरीदने के लिए नहीं।

आज के इस संक्रमण काल में हमें एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है: स्कूल प्रशासन की भूमिका: मैनेजमेंट को केवल बिजनेस नहीं देखना चाहिए। यदि शिक्षक सही है, तो प्रशासन को उसके पीछे चढ़ाने की तरह खड़ा होना चाहिए। जब छात्र देखता है

कि स्कूल मैनेजमेंट शिक्षक के साथ है, तो उसकी उम्मीद खलता कम होती है। काउंसिलिंग सत्र: हर स्कूल में न केवल छात्रों के लिए, बल्कि अभिभावकों के लिए भी कार्यशालाएं होनी चाहिए, जहाँ उन्हें बताया जाए कि "अत्यधिक सुरक्षा उनके बच्चे के भविष्य को अंग बना रही है।"

शिक्षक का सशक्तिकरण: शिक्षकों को आधुनिक तकनीक और कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट (विवाद प्रबंधन) की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे आक्रामक छात्रों या अभिभावकों को शालीनता और दृढ़ता से संभाल सकें।

1. **किष्कंध: आगे का रास्ता** शिक्षा कोई वस्तु नहीं है जिसे बजाकर से खरीदा जा सके। यह एक संस्कार है जिसे केवल विनम्रता से ग्रहण किया जा सकता है। यदि अभिभावक अपनी फीस के अहंकार में शिक्षक को छोटा समझेंगे, तो अंततः नुकसान उनके बच्चे का ही होगा, क्योंकि वह एक डिग्री तो पा लेगा, लेकिन संस्कार और चरित्र से शून्य रह जाएगा। शिक्षक को अपनी गरिमा वापस पाने के लिए खुद को बदलना होगा, और समाज को अपनी मानसिकता गुरु का स्थान पर्यार को लकीर न सही, लेकिन मार्गदर्शक की मशाल तो जरूर होना चाहिए।

"जिस समाज में शिक्षक भयभीत है और छात्र अनुशासनहीन, उस समाज का पतन निश्चित है। सुधार की शुरुआत घर के ड्राइंग रूम से होनी चाहिए, जहाँ शिक्षक के बारे में होने वाली चर्चा सम्मानजनक हो।"

-प्रोफेसर अशोक कुमार, पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय

हाईकोर्ट ने तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रु. किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी 16 साल से अकेले ही बच्चों का पालन-पोषण कर रही है, महिला के पास न आय है, न अपना घर है

जोधपुर, (कासं)। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाले स्थायी गुजारा भत्ते को 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार सुरोहित की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि पत्नी 16 सालों से अकेले बच्चों का पालन-पोषण कर रही है। महिला के पास न आय है, न अपना घर है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पति एक सरकारी डॉक्टर है, तो फैमिली कोर्ट का 25 लाख रुपए का पुराना फैसला न्यायोचित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता अमीरी का जरिया नहीं है, बल्कि सम्मान का अधिकार है।

यह मामला जोधपुर निवासी शोभा कंव्वर और डॉ. नरपतिसिंह के बीच चल रहे विवाद का है। दोनों की शादी 23 अप्रैल 1994 को मारवाड़

जंक्शन में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। इनके 2 बेटे हैं। पत्नी ने 2 मार्च 2015 को फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। पत्नी का आरोप है कि 2004 में पति और उसके परिवार पर पिता का मकान और जमीन बेचकर पैसे लाने का दबाव बनाया। इनकार करने पर 1 मई 2009 को पीटा गया और बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। इस मामले में देहेज प्रताड़ना, आचार्यक विश्वासघात, मारपीट और चड्यंत्र के तहत एफआईआर भी दर्ज है। फैमिली कोर्ट, जोधपुर ने तलाक की डिक्ली जारी करते हुए पति को पत्नी को 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया था और भुगतान होने तक 45 हजार रुपए प्रति माह देने के लिए कहा था। पत्नी ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए 2 करोड़ रुपये की मांग की, जबकि पति ने इसे अत्यधिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पति एक सरकारी डॉक्टर है, तो फैमिली कोर्ट का 25 लाख रुपए का पुराना फैसला न्यायोचित नहीं था, कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता अमीरी का जरिया नहीं है, बल्कि सम्मान का अधिकार है

यह मामला जोधपुर निवासी शोभा कंव्वर और डॉ. नरपतिसिंह के बीच चल रहे विवाद का है

महिला के वकील ने पैरवी करते हुए बताया कि पति ईएनटी विशेषज्ञ और सरकारी अस्पताल वाली में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। वेतन के अलावा निजी प्रैक्टिस, अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल एजेंसी से मिलकर उनकी 8-10 लाख रुपए मासिक आय है। पत्नी के पास आय का कोई साधन नहीं है। वह 16 साल से बच्चों को अकेले पाल रही है। वहीं, पति की ओर से वकील

ने तर्क दिया कि पत्नी बीए, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी योग्यताधारी वकील है। 50 हजार रुपए मंथली कमाती है। पति की बूढ़ी मां बीमार है और विकलांग भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हैं। ऐसे में पति पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।

दोनों पक्षों को दलीलें सुनकर खंडपीठ ने माना कि विवाद लगभग

15 साल तक चला और पत्नी 16 वर्षों से बच्चों को अकेले पाल रही है। कोर्ट ने पाया कि पति का वेतन लगभग 2 लाख रुपए मासिक प्रमाणात है। उसके पास स्वअर्जित मकान और पैरुत कुर्सी हैं। इसके विपरीत, पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आवास नहीं है। कोर्ट ने माना कि पत्नी की निजी प्रैक्टिस संबंधी आय के दस्तावेज 2011 से पुराने हैं और उसकी वर्तमान आय साबित नहीं होती है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी को दो करोड़ की मांग अत्यधिक और असमर्थित है, क्योंकि गुजारा भत्ता समृद्धि का जरिया नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का माध्यम है। कोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार और पति को अपील खारिज करते हुए स्थायी गुजारा भत्ता 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है।

प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मिले विस्तार, सरस को बनाए राष्ट्रीय ब्रांड : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डेयरी विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सशक्त धुरी है, जो किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि का आधार बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित डेयरी क्षेत्र के विकास को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऐसे में प्रदेश में डेयरी द्वारा दुग्ध संग्रहण एवं प्रसंस्करण अवसरचना के सुदृढीकरण के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हुए औसत दुग्ध संकलन एवं दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार किया जाए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को डेयरी क्षेत्र के विकास को लेकर बैठक ली। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में 2000 हजार करोड़ रुपये के राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड एवं सरस को राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर के साथ ही प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों व

पर्यटन स्थलों पर सरस आउटलेट खोले जाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादों की व्यापक ब्रांडिंग भी की जाए। शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए औचक निरीक्षण

किए जाएं एवं इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, अत्याधुनिक मिल्क टेरिगिंग मशीन एवं रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का सुदृढीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सहकारिता से समृद्धि के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने से किसानों को मजबूती मिलती है। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त विभागीय योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी एवं सुगम तरीके से दुग्ध उत्पादकों को अधिकारिक लाभ पहुंचाया जाए। साथ

■ 'प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर सरस आउटलेट खोलने के हो प्रयास'

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि "मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई करें, लापरवाही बरतने वालों पर भी हो सख्त कार्रवाई"

ही, तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए डेयरी क्षेत्र को और अधिक संगठित एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। बैठक में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से आरसीडीएफ के मुनाफे में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में आरसीडीएफ के औसत दुग्ध संकलन से लेकर दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन एवं विविधकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

16 नदी बेसिनों के विकास के लिए प्लान तैयार करें : वी. श्रीनिवास

जल संरक्षण कार्यों की तकनीकी प्लानिंग, सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश

जयपुर । मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में शुक्रवार को राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण और जल संसाधन के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। इसमें राज्य की 16 नदी बेसिनों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।

बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्राधिकरण के आयुक्त अभय कुमार ने कार्य और प्रगति से अवगत कराया। प्राधिकरण के मुख्य अभियंता राज पाल सिंह ने कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

मुख्य सचिव ने जल उपलब्धता के आकलन और उसके समुचित उपयोग में राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राज्य में प्राधिकरण के महत्व को देखते हुए 16 नदी बेसिनों के समग्र विकास के लिए बेसिन-वाइज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल की

कमी वाले क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा नदी बेसिन मास्टर प्लान की गाइडलाइन एवं

विकास से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही रिजर्वेशन मास्टर प्लान के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण,

जयपुर द्वारा प्रगति पर आधारित विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

मुख्य सचिव ने एमजेएसए 2.1 एवं 2.2 के तहत जल संरक्षण कार्यों की तकनीकी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मोबाइल एप आधारित ट्रेकिंग और सर्वे को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान नदियों के पुनर्जीवन (पुनरुद्धार) परियोजना, जल शक्ति अभियान, जल संयंत्र जन भागीदारी, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम तथा विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा कर निर्देश दिए। उन्होंने जिला पुनर्भरण योजना के तहत भूजल पुनर्भरण कार्यों को गति देने, जल संरक्षण में नवाचार अपनाने, नदियों के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने तथा इंदिरा गांधी नहर के मरम्मत कार्य और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

शारीरिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

जयपुर । राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित उप निरीक्षक (दूरसंचार) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 को लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है।

विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड मनोज कुमार ने बताया कि अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को लॉगिन करने के पश्चात रिजल्ट में पोर्टल पर जाना होगा।

आरपीएससी अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले विशेषज्ञों की लें सेवाएं : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 परीक्षा के दो उत्तरों को हटाने के आरपीएससी के निर्णय को गलत मानते हुए विशेषज्ञ के ज्ञान पर सवाल उठाया। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता के मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्ति पेश नहीं करने के कारण उसे राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी को कहा है कि वह अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले विषय विशेषज्ञों की ही सेवाएं लें। अदालत ने कहा कि एसाइ के जमाने में तथ्यहीन व गलत सूचनाओं के बजाय संचयन के आधार पर ही राय दी जानी चाहिए। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश पठन गर्ग

की याचिका को खारिज करते हुए दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरिहंत समदहिया ने परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों के 6 प्रश्नों के उत्तर को चुनौती दी थी। इनमें से एक प्रश्न था कि नागनाची मंदिर कहाँ है? जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने राजस्थान का इतिहास संबंधी पुस्तक के आधार पर कहा कि यह मंदिर बाडमेर के नामना गाँव में है और यह 1291 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसके विपरीत आरपीएससी के विशेषज्ञ ने मंदिर जोधपुर के किले व बाडमेर के गाँव दोनों जगह होने के आधार पर जोधपुर व बाडमेर दोनों उत्तरों को सही माना। इसी तरह एक प्रश्न था कि उत्तरी गोलार्द्ध में दुनिया की कितनी

आबादी है? जिसका उत्तर आरपीएससी ने विशेषज्ञ की राय के आधार पर 90 प्रतिशत को सही माना। कोर्ट के ध्यान में आया कि इनमें से एक प्रश्न के मामले में विशेषज्ञ को इतिहास की जानकारी नहीं है, जबकि एक प्रश्न के मामले में विशेषज्ञ ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के बजाय अखबार में प्रकाशित लेख के आधार पर राय दी। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि विशेषज्ञ को ज्ञान नहीं है और उसकी क्षमता संदेहास्पद है। कोर्ट ने कहा कि उसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है और आरपीएससी से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले विषय विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की अपेक्षा की जाती है।

समिति सदस्य को 2 साल से भत्ता क्यों नहीं दिया?

हाईकोर्ट ने बाल अधिकारिता आयुक्त को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने के आदेश दिए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर जिले की बाल कल्याण समिति की सदस्य को बीते दो साल से भत्ते का भुगतान नहीं करने पर 8 अप्रैल को बाल अधिकारिता आयुक्त एवं संयुक्त सचिव को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आयुक्त से यह स्पष्ट करने को कहा है कि याचिकाकर्ता सदस्य को बीते दो साल का बकाया भत्ते का भुगतान क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि तब तक विभाग चाहे तो बकाया भुगतान कर सकता है। अदालत ने कहा कि जब राज्य सरकार के वकील भुगतान नहीं करने का कारण बताते हैं

असमर्थ हैं तो यह उचित है कि विभाग के आयुक्त को बुलाकर उनसे इस संबंध में जानकारी ली जाए। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपौठ ने यह आदेश कविता शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता उमाशंकर पांडे ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जिला बाल कल्याण समिति में सदस्य के तौर पर अक्टूबर, 2023 में नियुक्त हुई थी। बाल अधिकारिता विभाग की ओर से समिति के सदस्यों को काम के बदले भत्ते का भुगतान किया जाता है। याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से मार्च,

2024 से याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की धनराशि भत्ते के तौर पर नहीं दी गई है।

जिसके चलते उसे वित्तीय परेशानी भी उठानी पड़ रही है। याचिका में कहा गया कि इस संबंध में विभाग में कई बार प्रार्थना पत्र पेश किए, लेकिन दो साल बीतने के बाद भी उसे बकाया भुगतान नहीं हुआ है। वहीं विभाग की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह इस संबंध में जानकारी देने में असमर्थ है। इस पर अदालत ने विभाग के आयुक्त को हाजिर होने के आदेश देते हुए कहा है कि विभाग चाहे तो बकाया भुगतान कर सकता है।

जयपुर सहित 18 शहरों में बारिश-ओलावृष्टि



राजधानी जयपुर में शुक्रवार शाम तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे।

फोटो-राष्ट्रदूत

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । पश्चिम विक्षोभ के असर से शुक्रवार को जयपुर सहित 18 शहरों में बारिश हुई। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर सहित अन्य कुछ शहरों में ओलावृष्टि देखने को मिली। इससे रबी की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। रैगिस्तानी इलाकों में ओलावृष्टि से कश्मीर देखा दृश्य बन गया।

मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, जैसलमेर-बीकानेर में ओलों की चादर बिछ गई। अजमेर-ब्यावर में आंधी से टीनशेड उड़ गए। जयपुर, नागौर, सीकर, कुचामन-डीडवाना और जालोर सहित कई जिलों में बारिश हुई। बारिश-ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई।

खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से पिछले 24 घंटों में कहीं-कहीं आंधी बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश पदमपुर, श्रीगंगानगर में 11.5 मिमी दर्ज की गई। सक्रिय विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन के साथ तेज आंधी (40-50किमी प्रतिघंटा) व बारिश दर्ज की गई तो वहीं कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी

हुई। 4 अप्रैल को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में तेज आंधी-बारिश व कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है। 5-6 अप्रैल को आंधी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होने तथा 7 अप्रैल को एक और नया मजबूत विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में पुनः तेज आंधी-बारिश गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है कि खुले आसमान में पककर तैयार फसलों, कृषि मंडियों व धान मंडियों में खुले में रखे हुए अनाज व जिनसे को ढककर रखें या सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके।

पुलिस कमिश्नर आज करेंगे जनसुनवाई

जयपुर। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल आज पुलिस थाना शिवदासपुर में जनसुनवाई करेंगे। यह जनसुनवाई दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें चाकसू सफिल के चाकसू, शिवदासपुर, सांगानेर सदर और कोटाखवादा थाना क्षेत्रों के परिवारियों की समस्याएं सुनी जाएंगी।

श्री महावीर साधना संस्थान की अपील खारिज

जयपुर (कास)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1, महानगर प्रथम ने श्री महावीर साधना संस्थान को आवंटित जमीन के उपयोग के मामले में सिविल कोर्ट के आदेश में दखल देने से मना करते हुए उसे बरकरार रखा है।

अदालत ने कहा कि सिविल कोर्ट का आदेश अपीलार्थी संस्थान की ओर से विवादित स्थल पर एक धर्म विशेष की मूर्तियां स्थापित करने और उसका उपयोग भी धर्म विशेष के लिए करने का तथ्य प्रमाणित करता है। ऐसे में निचली कोर्ट ने यह आदेश प्रार्थियों के पक्ष में सही तय किया है और इस आदेश की पुष्टि की जाती है। एडीजे कोर्ट ने यह आदेश श्री महावीर साधना संस्थान की अपील को सारहीन मानकर खारिज करते हुए दिया।

अपील में कहा कि अप्राथी संस्थान सभी काम जनहित में करवा रही है और वहां पर योग ध्यान केन्द्र भी चल रहा है। ऐसे में निचली कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए,

■ सिविल कोर्ट का आदेश बरकरार

लेकिन एडीजे कोर्ट ने संस्थान की दलील नहीं मानी और निचली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।

दरअसल सिविल कोर्ट ने शशि माथुर के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर 25 मार्च 2026 को फैसला देते हुए कहा था कि सामुदायिक केन्द्र के लिए आवंटित जमीन का उपयोग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं हो सकता और न ही वहां पर उस धर्म विशेष की मूर्तियां ही स्थापित हो सकती हैं। वहीं कोर्ट ने श्री महावीर साधना संस्थान के सचिव को पार्वत किया था कि वह उसे आवंटित जमीन का उपयोग करने और उसकी सुविधाओं के उपयोग करने के लिए आमजन को वंचित नहीं करे।

जमीन पर एक धर्म विशेष की मूर्तियां स्थापित नहीं करे और न ही इसका उपयोग किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए करे।

“गहलोत-राठौड़ के बीच में मैं नहीं पडूंगा”

75 साल की राजनीति पर घनश्याम तिववाड़ी ने संतुलित प्रतिक्रिया दी

जयपुर। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिववाड़ी ने राजनीति में 75 वर्ष के बाद सन्यास के फॉर्मूले को लेकर चल रही बहस पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ दोनों ही विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए वे इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते।

तिववाड़ी ने स्पष्ट किया कि मोहन भागवत ने कभी भी राजनीति में उम्र के आधार पर कोई फॉर्मूला तय नहीं किया। उन्होंने खुद भी कहा है कि न तो वे रिटायर हो रहे हैं और न ही किसी को रिटायर होने के लिए कह रहे हैं। दरअसल, मंगलवार को मदन राठौड़ ने

■ तिववाड़ी ने कहा कि 'भागवत ने राजनीति में उम्र का कोई फॉर्मूला तय नहीं किया है'

अशोक गहलोत को 75 साल की उम्र पर करने के बाद सन्यास लेने की सलाह दी थी। इसके जवाब में गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि यह फॉर्मूला अगर लागू होता है तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर भी लागू होना चाहिए, उन पर नहीं। गहलोत ने यह भी कहा कि वे 100 साल तक जनता की सेवा करते रहेंगे।

आदर्श क्रेडिट सोसायटी घोटाले के आरोपियों और राजस्थान सरकार का वकील एक ही हैं, पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? : नेता प्रतिपक्ष

टीकाराम जूली ने प्रेस कॉफ्रेंस कर राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा और उनकी लॉ फर्म "ऑरा एंड कंपनी" की भूमिका पर सवाल उठाया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को प्रेस कॉफ्रेंस कर राजस्थान की लाखों गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों का पैसा हड़पने वाले बहुचर्चित आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा तथा उनकी लॉ फर्म ऑरा एंड कंपनी की भूमिका पर सवाल उठाया है।



नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

जूली ने कहा कि इस घोटाले के आरोपियों और राज्य सरकार का वकील एक ही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस घोटाले के पीड़ितों के साथ डबल गेम खेल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्ष 1999 में मुकेश मोदी और उनके परिवार द्वारा शुरू की गई इस सोसाइटी ने 2010 से 2014 के बीच करीब 22 लाख मामूली लोगों से 15 हजार करोड़ रुपये की टांगी की। जांच में सामने आया कि लगभग 125 फर्जी (शैल) कंपनियों के माध्यम से जनता का पैसा मोदी परिवार के सदस्यों और उनके करीबियों तक पहुंचाया गया। बाद 2018 में की गई एआईआर के चार्ज गिरफ्तारियां तो हुईं, लेकिन आज न्याय की उम्मीद पर सरकार के वकील ही पानी फेर रहे हैं।

जूली ने बताया कि अन्य आरोपियों के अतिरिक्त इसमें एक आरोपी सिद्धार्थ चौहान भी शामिल है। राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे शिवमंगल शर्मा और उनकी लॉ फर्म ऑरा एंड कंपनी का इस घोटाले के आरोपियों के साथ गहरा संबंध है। उन्होंने बताया कि इसी घोटाले में दो और मुकदमे गुडगांव एवं दिल्ली में चल रहे हैं। इन मुकदमों में सिद्धार्थ चौहान सह आरोपी हैं एवं अभी तक फरार होने के कारण भगौडा घोषित किया जा चुका है।

■ उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले के सह आरोपी सिद्धार्थ चौहान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे में पैरवी के लिए लॉ फर्म "ऑरा एंड कंपनी" नियुक्त है, जो वकील शिवमंगल शर्मा, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल तथा इनके साथियों की फर्म है। उन्होंने सवाल उठाया कि, "यह कैसे संभव है कि एक तरफ वही वकील दिल्ली में घोटाले के आरोपी को बचाने की पैरवी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से पीड़ितों का पक्ष रखने का ढोंग कर रहे हैं?"

■ जूली ने कहा कि "यह कैसे संभव है कि एक तरफ वही वकील दिल्ली में घोटाले के आरोपी को बचाने की पैरवी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से पीड़ितों का पक्ष रखने का ढोंग कर रहे हैं?"

इस आरोपी सिद्धार्थ चौहान के दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे में आरोपी की ओर से लॉ फर्म लिंग "ऑरा एंड कंपनी" नियुक्त है जो वकील शिवमंगल शर्मा, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल तथा इनके साथियों की फर्म है। उन्होंने सवाल उठाया कि, "यह कैसे संभव है कि एक तरफ वही वकील दिल्ली में घोटाले के आरोपी को बचाने की पैरवी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से पीड़ितों का पक्ष रखने का ढोंग कर रहे हैं?" यह सीधे तौर पर हितों के टकराव का मामला है और

पैसा गँवा चुके निवेशकों की आंखों में धूल झोंकना है। जूली ने कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बार कार्डिसल ऑफ इंडिया का नियम 33 स्पष्ट रूप से किसी भी वकील को विरोधी हितों वाले पक्षों के लिए कार्य करने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चंद्र प्रकाश त्यागी बनाम बनारसी दास मामले में व्यवस्था दी है कि वकील और क्लाइंट का संबंध विश्वास पर टिका होता है। जब वकील के पास दोनों पक्षों की गोपनीय जानकारी हों, तो न्याय

की निष्पक्षता खत्म हो जाती है। जूली ने कहा कि एक ही घोटाले से जुड़े मामलों में एक वकील दिल्ली हाईकोर्ट में सह-आरोपी की पैरवी कर रहा हो और वहीं सुप्रीम कोर्ट में उसी प्रकरण से जुड़े राज्य पक्ष (केस) में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में उपस्थित हो, तो यह स्थिति स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की श्रेणी में आती है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि क्या अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा और ऑरा लॉ फर्म ने राजस्थान सरकार को यह जानकारी दी थी कि वे इसी घोटाले के सह-आरोपी के वकील के रूप में भी कार्य कर रहे हैं? यदि सरकार को इस तथ्य की जानकारी दी गई थी, तो फिर ऐसे हितों के टकराव वाले वकील को राज्य का पक्ष रखने के लिए नियुक्त करना पीड़ितों के साथ सरासर धोखा है। और यदि वकील द्वारा यह जानकारी छिपाई गई, तो क्या राजस्थान सरकार अब उल्टे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला दर्ज करने का साहस दिखाएगी?

जोधपुर : कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई लोगों से छह करोड़ की धोखाधड़ी

कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ा मुनाफा और एजेंट के तौर पर काम करने का प्रलोभन दिया था

जोधपुर, (कासं)। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 18 ई में रहने वाले व्यक्ति से कुछ लोगों ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ा मुनाफा और एजेंट के तौर पर काम करने का प्रलोभन देकर पांच-छह करोड़ का फ्रांड कर लिया। पीड़ित ने अदालत की शरण लेकर अब महामंदिर थाने में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने घटना में अब अग्रिम जांच आरंभ की है। मामले में रमेश पुरी पुत्र भीमपुरी ने रिपोर्ट दी।

रिपोर्ट में समुद्र जीवन मल्टी स्टेट मल्टी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन सोसाईटी लिमिटेड एवं समुद्र जीवन फुड्स इण्डिया लिमिटेड के डायरेक्टर महेश किशन मोतेवार और अन्य पर आरोप लगाया गया है। वैशाली मोतेवार, राजेश पंडूरंग, विनोद डांगी, राजस्थान यूनिट हेड, निवासी गांव बीबीसर जिला झुन्डुन, राजेश मात्रे निवासी पुणे, प्रभाद पारसवार घनश्याम, जसभाई, सोमनाथ, अरुण भालेराव

■ आरोपियों ने झांसा दिया था कि कम्पनी भारत में करीब 16 राज्यों में हर तरह का व्यवसाय करती है तथा उसका काफी अच्छा मुनाफा देती है

■ पीड़ित ने अदालत की शरण लेकर महामंदिर थाने में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी, पुलिस ने जांच शुरू की

पारसवार, लीला महेश मोतेवार, अभिषेक मोतेवार एवं राजेश को भी नामजद किया गया है। पीड़ित ने बताया कि विनोद डांगी नाम के व्यक्ति ने मेरे व मेरे अन्य साथियों से सम्पर्क कर बताया कि वह समुद्र जीवन फुड्स इण्डिया लिमिटेड व समुद्र जीवन मल्टी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन सोसाईटी लिमिटेड जिसका ऑफिस मैं पावटा सनसिटी अस्पताल के पास रखा तथा इसका मुख्यालय पुणे में है। कम्पनी भारत में करीब 16 राज्यों में हर तरह का व्यवसाय करती है तथा उसका काफी अच्छा मुनाफा देती है। आप भी हमसे जुड़ें और अपना निवेश

करें व एजेंट के रूप में अन्य लोगों का निवेश कराओं, जिस पर मैं व मेरे अलावा कुशालाराम सोलंकी, हनुमानाराम, सुन्दन बोराणा, कैलाश राव, प्रेमराम, रूपाराम, बाबूलाल जांगिड़, अब्दुल मुजीब, अनिता बोराणा, जेटमल, पूजा बोराणा व रमेश पुरी हम सब उनसे मिलने उनके पावटा ऑफिस गए। तब विनोद डांगी ने बताया कि कम्पनी का एक पेपर चलता है, टीवी चैनल व होटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल, बकरी व भैंस पालन, कृषि कार्य आदि का कार्य करती है। जिस पर विनोद डांगी पर विश्वास करके उनके डायरेक्टर व सह

डायरेक्टर व कम्पनी के अन्य अधिकारियों से बात की। इसके बाद अधिकारियों ने हमें पुणे बुलाया तथा हम सब के साथ उन्होंने मिटिंग की, जिसमें कम्पनी के डायरेक्टर महेश किशन मोतेवार, वैशाली महेश किशन गोलेवार, राजेश पाण्डूरंग भण्डारे, घनश्याम, राजेश, जस भाई, राजेश मात्रे, सोमनाथ, अरुण भालेवार, प्रसाद पारारवार, लीला महेश किशन मोतेवार, अभिषेक मोतेवार पुत्र महेश किशन मोतेवार आदि ने हम लोगों से काफी बातचीत की व अपने व्यवसाय के बारे में बताया व हमें अपनी कम्पनी में इन्वेस्ट करने व एजेंट के रूप में कार्य करने को कहा, इस पर हमने उनकी झूठी बातों पर विश्वास करते हुए एजेंट के रूप में कार्य करना आरम्भ किया।

पीड़ित ने बताया कि जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से व स्वयं के रूप में एकत्रित करके किशतों व एक मुस्त करीब 5 से 6 करोड़ रूपए विनोद डांगी व कम्पनी के कार्यालय में जमा करवाए तथा उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा

कि हमारी योजना की अवधि पूर्ण होने पर कम्पनी द्वारा आप लोगों के जमा राशि मुनाफा सहित आपके बैंक खातों में जमा हो जाएगी तथा एक बार महेश किशन मोतेवार जोधपुर आया तथा हमसे मुलाकात की। बाद में हमें अजमेर के पास कैकड़ी में 700-800 बीघा जमीन पर बकरी पालन, भैंस पालन व अन्य कृषि कार्यों के बारे में बताया तथा हमें वहां ले जाकर विजिट भी करवाई और उन्होंने कहा कि जोधपुर के आसपास गांवों में बड़ी जमीन देख लो, जिसमें ये ही कार्य करेंगे, जिसकी देखरेख आप लोग करोगे। इनकी लालच भरी बातों व झूठे प्रलोभन में आ गए और कराड़ों रूपये इनके पास जमा करवा दिए। जब समयावधि पूर्ण हो गयी तो किसी के खाते में पैसे नहीं आया, तब हमने विनोद डांगी व अन्य कम्पनी के अधिकारियों से इस संबंध में बात की तो वे लोग टालम टालकर व झंसे देते रहे। बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। इस तरह उन लोगों ने पांच छह करोड़ का फ्रांड किया।

रामगंजमंडी में अंधड़ से बिजली आपूर्ति ठप, जलापूर्ति बाधित

रामगंजमंडी, (निस्)। रामगंजमंडी पेयजल परियोजना के अंतर्गत राणाप्रताप सागर बांध स्थित आम्बाकुई इंटेक वेल पर बीती रात आए तेज अंधड़

■ पावर लाइन के सुधार एवं मटेनेंस का कार्य जारी

एवं बारिश के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। जानकारी के अनुसार 33केवी लाइन का तार टूटने से शुरूवार प्रातः लगभग 6.40 बजे से पावर सप्लाई बंद है, जो देर शाम तक चालू नहीं हो सकी है।

विद्युत विभाग द्वारा उक्त पावर लाइन के सुधार एवं मटेनेंस का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण वीटी पम्प भी बंद है, जिससे जल उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है। इस स्थिति के चलते चार अप्रैल शनिवार को रामगंजमंडी शहर सहित सातलखेड़ी, खैराबाद, चेचट, मोडक स्टेशन, मोडक गांव एवं परियोजना से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातःकालीन जलापूर्ति बाधित रहेगी।

डूंगरपुर में विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या की

डूंगरपुर, (निस्)। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव में शुक्रवार को एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका की पहचान सीमा के

श्रीगंगानगर, (निस्)। पदमपुर कस्बे के चाई नंबर 16 में 2 अप्रैल को एक लड़की की शादी को बाल विवाह मानकर रकवा दिया गया है। लड़की की उम्र 18 वर्ष से 5 माह कम थी। उसकी बारात भी बीकानेर से दरवाजे तक आ चुकी थी। बाल कल्याण समिति और पदमपुर पुलिस ने यह शादी लड़की के 18 वर्ष की हो जाने के बाद करने के लिए परिवार वालों को पाबंद किया है। हालांकि दूल्हे ने तर्क दिया कि वे तो सगाई करने आए हैं। शादी तो नवंबर माह में करेंगे, लेकिन अधिकारियों ने युवक के दूल्हे के वस्त्र पहनकर और बारात के बाहनों पर लगे स्टीकर, शादी के कार्ड आदि दिखाए तो दूल्हा भी सकपका गया।

चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक त्रिलोक वर्मा ने बताया कि इस संबंध में चाइल्ड हेल्प लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल आई थी। मिली सूचना की प्रारंभिक तस्दीक करवाने के बाद 2 अप्रैल को शादी होने

■ बाल कल्याण समिति और पदमपुर पुलिस ने यह शादी लड़की के 18 वर्ष की हो जाने के बाद करने के लिए परिवार वालों को पाबंद किया

का पता चला। गुरुवार को समिति अध्यक्ष जोगेंद्र कौशिक, सदस्य आनंद मारवाल, वंदना गौड़, राजस्व पटवारी अकेश खुडिया, पदमपुर एसएचओ सुमन जयपाल, ड्यूटी ऑफिसर बाल कल्याण अधिकारी एसएसआई हरजिंद सिंह मय जाब्ता विवाह स्थल पर पहुंचे। टीम के पहुंचने से पहले बीकानेर से बारात दूल्हन के घर तक पहुंच चुकी थी। बारात के स्वागत के बाद मेहमान भोजन ग्रहण कर रहे थे। इधर फेरों की तैयारी थी। टीम ने दुल्हन के जन्म प्रमाण

पत्र संबंधी दस्तावेज मांगे। माता-पिता की ओर से जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत किए। इसमें दुल्हन की जन्म तिथि 25 अगस्त 2008 थी। उस पर लड़की की उम्र 18 वर्ष से 5 माह और 23 दिन कम थी। प्रश्नान्वेदन पर परिवार को यह शादी लड़की के 18 वर्ष की होने तक नहीं करने को पाबंद किया। परिजन लड़की की शादी जगह या समय बदल कर नहीं कर दें, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई है। एसएचओ सुमन जयपाल ने दूल्हे सहित उसके परिवार के सदस्यों को थाने ले जाकर कानून के बारे में जानकारी दी। इधर शादी करवाने आए पंडित पुलिस और बाल कल्याण समिति की टीम को देखकर मौके से फरार हो गया। वहीं हलवाई और टेंट के संबंधक को पुलिस ने कानून के बारे में बताया और आगे से बुकिंग से पहले डेकाले-लड़की के बालिंग होने के प्रमाण देखकर ही शादी के कार्यक्रम की बुकिंग के लिए पाबंद किया।

युवक ने सुसाईड किया

डूंगरपुर, (निस्)। चौरासी थाना क्षेत्र के वासुवा गांव में एक युवक ने मवेशी घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान सुखदेव मनात के रूप में हुई है, जो दो दिन पहले ही अहमदाबाद से अपने घर आया था। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वासुआ निवासी प्रताप मनात की इस्तेमाल बायक जन्म की है। धरनावदा पुलिस ने बताया कि झगर चौकी पुलिस द्वारा धरनावदा-छबड़ा रोड स्थित चाली नदी पुलिया के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी की। चौकिंग के दौरान छबड़ा की ओर से एक काले रंग की बजाज पल्सर

छबड़ा में भूमाफिया ने वर्षों पुराने तालाब पर कब्जा किया

छबड़ा, (निस्)। पूर्व विधायक करणसिंह राठौड़ ने धींगराड़ी में वर्षों पुराने तालाब को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

राठौड़ ने बताया कि खसरा नंबर 234/1 में स्थित तालाब का निर्माण मनरेगा योजना एवं भैरोसिंह शेखावत के कार्यकाल में काम के बदले अनाज योजना के लाखों रुपए खर्च कर के

■ पूर्व विधायक ने तालाब को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा



छबड़ा के धींगराड़ी में वर्षों पुराने तालाब पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया।

लोगों द्वारा तालाब तहसील में मिलीभागत कर कब्जा कर लिया गया है। जिस खसरा नंबर 234/1 पर आज तक किसी ने नो काश्त नहीं की, उसको भूमाफियाओं ने किसी बाहरी व्यक्ति की जमीन का एलेंटमेंट करवा कर सड़क के किनारे स्थित तालाब पर खाते

में दर्ज कर लिया, जो बेशकीमती है। राठौड़ ने कहा कि तालाब को पूरा गांव वला से पशु पेयजल के लिए काम में लेता आया है। भूमाफियाओं की प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त होने पर सार्वजनिक संपत्ति को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राठौड़ ने एसडीएम और

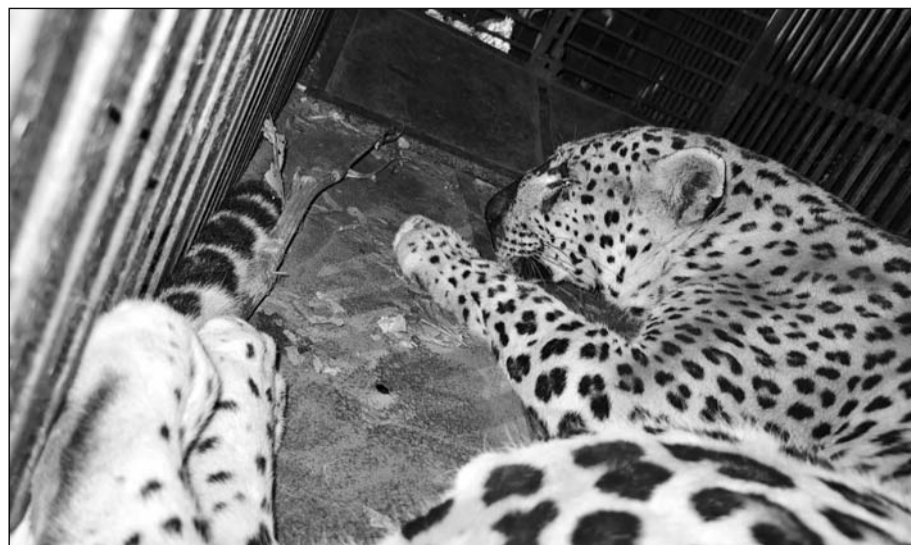
जिला कलेक्टर से उक्त सम्पूर्ण प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की है और अतिक्रमण से मुक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों के साथ इसको मुक्त करने का आंदोलन किया जाएगा।

एमपी पुलिस ने छबड़ा निवासी तस्कर को डोडा-चूरा सहित पकड़ा

■ आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया

मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे एक बोरा बंधा हुआ था। पुलिस द्वारा वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक द्वारा वाहन न रोकते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस बल ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पृष्ठताछ में इडवार ने अपना नाम

लालसोट के गोल गांव से मादा लैपर्ड को पकड़ा



वन विभाग की टीम ने सतर्कता से लैपर्ड को पिंजरे में काबू कर लिया।

लालसोट, (निस्)। आंतरी क्षेत्र में गोल गांव आबादी क्षेत्र में बीच लैपर्ड की दस्तक ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। कई दिनों तक ग्रामीणों की नींद उड़ी रही, लेकिन वन विभाग की सतर्कता से आखिरकार इस लैपर्ड को काबू कर लिया गया।

रेंजर रामकिशन मीणा के अनुसार 27 मार्च को ग्रामीणों ने लैपर्ड की मुवमेंट की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाकर लैपर्ड की मौजूदगी की पुष्टि की। इसके बाद गांव के पास स्थित

छबड़ा के मजदूर की बाइमेर में संदिग्ध मौत

छबड़ा, (निस्)। छबड़ा के सेमला निवासी एक मजदूर की बाइमेर जिले के ग्राम हड़वा तहसील शिव में संदिग्ध परिस्थितियों में आकस्मिक मौत हो जाने का मामला सामने आया है। घटना के कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे परिजनों एवं ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

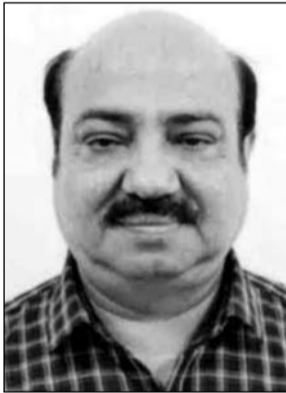
प्राप्त जानकारी के अनुसार रोडू लाल (45) पुत्र मथुरा लाल की आजीविका की तलाश में कुछ समय पूर्व बाइमेर गए थे, जहां वे एक कंपनी में टेकेदार के अधीन मजदूरी कार्य कर रहे थे। मंगलवार सुबह लगभग आठ बजे उनके छोटे भाई विनोद लोधा को फोन के माध्यम से उनके निधन की सूचना मिली, किंतु मृत्यु के कारणों के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। अचानक हुई इस दुखद घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोडू लाल परिवार के एकमात्र मुख्य कमाने वाले सदस्य था, ऐसे में उनके असाभ्यक्त निधन से परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

■ कई दिनों तक आबादी क्षेत्र के बीच लैपर्ड ने दहशत फैला रखी थी

पीएचसी के नजदीक पहाड़ी की तलहटी में पिंजरा लगाया गया और लगातार निगरानी शुरू कर दी गई। कई दिनों की घेराबंदी के बाद गुरुवार रात ऑपरेशन सफल हुआ और लैपर्ड पिंजरे में कैद हो गया। जैसे ही खबर फैली, मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति को विगड़ता देख

वन विभाग की टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए भीड़ को हटाया और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया। पिंजरे में कैद लैपर्ड को सुरक्षित वन विभाग की गाड़ी में रखकर लालसोट वन कार्यालय लाया गया। जांच में यह करीब डेढ़ साल की स्वस्थ मादा लैपर्ड पाई गई। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वन विभाग ने बिना देर किए इस लैपर्ड को सरिस्का के घने जंगलों में छोड़ दिया। समय रहते हुए इस ऑपरेशन से बड़ा हारसा टल गया और गोल गांव सहित आसपास के इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली।

राज. राजस्व मंडल के सदस्य किशोर कुमार का निधन



किशोर कुमार (फाईल फोटो)।

अजमेर/जयपुर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं राजस्थान राजस्व मंडल के सदस्य किशोर कुमार का जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।

बताया जा रहा है कि किशोर कुमार की तबीयत खैरथल जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अचानक खराब हो गई थी। स्वास्थ्य कारणों के चलते उनका तबादला बाद में अजमेर स्थित राजस्व मंडल में सदस्य के पद पर कर दिया गया था, जहां वे हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति के लिए किशोर कुमार मूल रूप से जयपुर के दुर्गापुरा क्षेत्र के निवासी थे, लेकिन उनका अजमेर से गहरा जुड़ाव रहा। उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर में अजमेर में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे डीएसओ, एडीएम सिटी, अजमेर विकास प्राधिकरण में सचिव सहित कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके थे। उनके

पत्थर ले जाते वाहन जब्त

कोटा, (निस्)। नान्ता पुलिस टीम व खनिज विभाग टीम ने संयुक्त रूप से इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से पत्थर परिवहन करते दो डंपर व 15 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि नान्ता थाने के थानाधिकारी महेश कुमार गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम व खनिज विभाग के खनी कार्यदेशक प्रथम गोविन्द प्रसाद शर्मा की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए नान्ता क्षेत्र में मैसैनेरी स्टोन (पत्थर) से भरे हुए बिना रवन्ना पाये जाने पर दो डंपर व 15 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है।

डूंगरपुर में एक दर्जन से अधिक सायबर ठग गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निस्)। जिला पुलिस द्वारा सायबर ठगों के खिलाफ पुलिस थाना टीमों की संयुक्त कार्रवाई में एक बाल अपचारी को डिटैन कर, 13 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनकी निशानदेही पर कई वाहन, मोबाइल, सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी आमजन को ठगने के लिए खंडहर,

■ आरोपियों की निशानदेही पर वाहन, मोबाइल, सिम कार्ड बरामद

जंगलों, खेतों के मचान, डेम के पास टापू का उपयोग करते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिलेभर में सायबर ठगों की कार्यवाही से कई नागरिक शिकार हो रहे थे। आरोपियों की इस बड़ती गतिविधियों को लेकर दोवड़ा, आसपुर, साबला तथा जिला विशेष टीम के कई तीनों दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को उनकी धरपकड़ के लिए लगाया गया, जो एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर आमजन से करोड़ों रुपए ठगी कर रहे थे। इसी सूचना के आधार पर जिला सायबर सेल के कॉर्नि. हेमेंद्र



पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सिम कार्ड व मोबाइल जब्त किए।

सिंह को सूचना मिली कि आसपुर क्षेत्र के सोम कमला आंबा डेम के किनारे पर बने टापू कुछ लड़के बैटकर सायबर ठगी कर रहे हैं। मिली सूचना के आधार पर उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस थाना आसपुर, दोवड़ा, साबला तथा सायबर सेल की विशेष टीमों द्वारा फतेहपुरा अमृतिया होते हुए सोम कमला आंबा डेम के कमलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे से जा रहे रास्ते पर डेम के टापू के पास करीब 10-12 लड़के पेड़ों के पीछे तथा उनके द्वारा मोबाइल का लगातार

उपयोग किया जा रहा था जिसपर सभी टीमों ने घेरा डालकर इनकी बातों का सत्यापन किया। पुलिस ने जब इनकी पूछताछ करने पर संतोषपद जवाब नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस ने उनके मोबाइलों की डिटेल चेक की। साथ ही उनके बैंक खातों की भी जांच की गई, जिस पर यह पुष्टि हो गई कि फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी कर रहे हैं। यही नहीं वे ग्राहकों को अश्लील फोटो दिखाकर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में नरेश पुत्र मेघजी

पाटीदार, गणेश पुत्र भूरालाल पाटीदार, मेहुल पुत्र देवीलाल सुथार, गणेश पुत्र लालजी पाटीदार, प्रकाश पुत्र मनजी पाटीदार, विजय पुत्र पेमजी पाटीदार, हितेश पुत्र देवेग पाटीदार, तेजपाल पुत्र लालजी पटेल, दिनेश पुत्र अमरजी पाटीदार, नरेश पुत्र अमरजी पाटीदार, भावेश पुत्र हीरालाल पाटीदार, मनीष पुत्र मोगजी पाटीदार, एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटैन कर उनके कब्जे से थार जीप, मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड तथा रुपए बरामद किए।



बोधना शिवानंदन
राष्ट्रदूत बीकानेर, 4 अप्रैल, 2026 5

शतरंज में भारतीय खिलाड़ियों का बोल बाला देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में 11 साल की भारतवंशी बच्ची बोधना शिवानंदन ने इतिहास रच दिया है। बोधना शिवानंदन ने पापा के पुराने शतरंज बोर्ड से खेल की शुरुआत की, यूट्यूब से शतरंज की बारिकियां सीखीं और अब 2366 की बेहतरीन रेटिंग के साथ इंग्लैंड की नंबर-1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गईं हैं। उनके जुनून, परिवार का साथ और आत्मविश्वास ने उन्हें शिखर तक पहुंचाया। बोधना शिवानंदन को जहाँ भारत से है।

क्या आप जानते हैं?... सचिन तेंदुलकर 90 और 99 के स्कोर के बीच नौ बार आउट हुए हैं।

अभिषेक शर्मा पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना



नई दिल्ली, 3 अप्रैल। सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा पर आईपीएल मैच के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ गुरुवार को इंडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में उन्होंने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, जिसके चलते उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है।

अभिषेक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आईपीएल द्वारा जारी बयान के अनुसार, उन्होंने लेवल-1 के अपराध के तहत मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को मंजूर कर लिया है। अभिषेक शर्मा को आईपीएल की आचार संहिता के आर्टिकल 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। यह आर्टिकल आमतौर पर मैच के दौरान अनुचित व्यवहार या खेल भावना के विपरीत कमेंट्स या इशारों से संबंधित होता है।

कप्तान श्रेयस की फिफ्टी

चेन्नई, 3 अप्रैल। पंजाब किंग्स ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। एमएचिंदरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 209 रन बनाए। इसके जवाब में प्रियांश ने टीम को धमकाकर शुरुआत दिलाई। इसके बाद कूपर कॉलोनी, प्रभसिमरन और कप्तान श्रेयस अख्यर की दमदार पारियों की बदौलत किंग्स ने 8 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। पंजाब ने 18.4 ओवर में 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए।

210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने दमदार शुरुआत की। प्रियांश आर्या 11 गेंद में 39 रन की तुफानी पारी खेलकर आउट हुए। प्रभसिमरन ने 34 गेंद में 43 और कूपर कॉलोनी ने 22 गेंद में 36 रन का योगदान दिया। कप्तान श्रेयस अख्यर ने 29 गेंद में 50 रन की पारी खेली। नेहल 10 रन ही बना सके।

चेन्नई सुपर किंग्स ने शुक्रवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 203 रन बनाए। चेन्नई की ओर से आयुष म्हात्रे ने सर्वाधिक 73 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया।



किंग्स को शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने संजू सैमसन (सात) को आउट कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये आयुष म्हात्रे ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 96 रन जोड़े। 12वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने ऋतुराज गायकवाड को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। ऋतुराज गायकवाड ने 22 गेंदों में दो चौके लगाते हुए 28 रन बनाये। अगले ही ओवर में विजयकुमार वैशक ने आयुष म्हात्रे का भी शिकार कर लिया। आयुष म्हात्रे ने 43 गेंदों में पांच छक्के और छह चौके लगाते हुए 73 रनों की पारी खेली।

कार्तिक शर्मा एक रन बनाकर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए। सरफराज खान ने 12 गेंदों में छह चौके और एक छक्का लगाते हुए 32 रन बनाये। उन्हें विजयकुमार वैशक ने आउट किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 209 रनों का विशाल स्कोर बनाया। शिवम दुबे 27 गेंदों में पांच चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 45 रनों की पारी खेली। प्रशांत वीर छह रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब किंग्स के लिए विजयकुमार वैशक ने दो विकेट लिये। जेवियर बार्टलेट, मार्क यानसन और यजुवेंद्र चहल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

चेपाँक में गरजा आयुष का बल्ला, इस मैदान पर अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने म्हात्रे



चेन्नई, 3 अप्रैल। आईपीएल 2026 के सातवें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की भिड़ंत शुक्रवार को एमएचिंदरम स्टेडियम में पंजाब किंग्स (पीकेएस) के साथ हुई।

सीएसके के बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। आयुष एमएचिंदरम के मैदान पर अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। आयुष ने चेन्नई सुपर किंग्स के घरेलू मैदान एमएचिंदरम में 18

साल 261 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया। आयुष ने 19 साल की उम्र से पहले आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 से अधिक रनों की पारी खेलने के मामले में पृथ्वी शां की बराबरी भी कर ली है।

आयुष ने दूसरी बार आईपीएल में पचास रनों का आंकड़ा पार किया है। वहीं, पृथ्वी शां ने भी 19 साल की उम्र से पहले 2 बार आईपीएल में 50 से अधिक रनों की पारी खेली है। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी (3 पचास प्लस स्कोर) पहले स्थान पर हैं।

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने संजीव गोयनका पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में हैं। ललित मोदी ने आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स (एनएसजी) के मालिक संजीव गोयनका के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से टीम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये पहली बार नहीं है जब ललित मोदी ने गोयनका पर निशाना साधा है। इससे पहले भी वह लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक पर अपनी भड़सा निकाल चुके हैं। मालूम हो कि ललित मोदी को भण्डा घोषित किया जा चुका है और वह लंबे समय से देश से बाहर है।



ललित मोदी ने एक्स पर लिखा, मैंने आपसे कहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका आईपीएल में टीम के मालिक बनने के लायक नहीं हैं। मैं उनके बर्ताव से सच में शर्मिंदा हूँ। मैंने आईपीएल को फैंस और खिलाड़ियों दोनों के लिए बनाया था, न कि हर बार, हर साल ऐसा होने के लिए। अगर मैं अभी भी चेयरमैन और कमिश्नर होता तो मैं उसे तुरंत बैन कर देता और टीम का मालिकाना हक हमेशा के लिए छीन लेता। गोयनका घमंडी हैं। इसी मुद्दे के लिए फैंस/खिलाड़ी अनुबंध में एक क्लॉज है। बीसीसीआई इसे लागू करे, ईमानदारी सबसे ऊपर रहे। फैंस और खिलाड़ी दोनों इसे याद रखेंगे।

पाकिस्तान सुपर लीग में मोइन अली और डेविड वॉर्नर की हुई झड़प?

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीजन शुरुआत से ही विवादों से घिरा रहा है। कभी खिलाड़ी मैदान पर बॉल टैरिंग करते पकड़े जाते हैं तो कभी होटल में सुरक्षा को तार-तार किया जाता है। वहीं अब ताजा मामला ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और इंग्लैंड के मोइन अली से जुड़ा है। जहां हाल ही में इन दोनों खिलाड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब इस वीडियो को

सच्चाई खुद वॉर्नर ने बताई है। पाकिस्तान सुपर लीग में डेविड वॉर्नर कराची किंग्स के कप्तान हैं। वहीं मोइन अली उन्ही की टीम का हिस्सा हैं। ये घटना कराची वर्सेस रावलपिंडी मैच की सुरक्षा को तार-तार किया जाता है। वहीं अब ताजा मामला ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और इंग्लैंड के मोइन अली से जुड़ा है। जहां हाल ही में इन दोनों खिलाड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब इस वीडियो को

2027 से बढ़ जाएगी आईपीएल मैचों की संख्या? द्विपक्षीय सीरीज में आएगी कमी : अरुण धूमल

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। आईपीएल का 19वां सीजन खेला जा रहा है जिसके अभी तक 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। वहीं आज, 3 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत होगी।

31 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन अगले साल यानी 2027 में आईपीएल मैचों की संख्या बढ़ सकती है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा है कि आईपीएल विंडो बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

आईपीएल में जब 8 टीमों खेलती थी तो हर टीम उस समय 2-2 मैच खेलती थी। लेकिन 2022 में दो टीमों लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के शामिल होने से कुल टीमों की संख्या 10 हो गई और अब लीग स्टेज में हर टीम सभी टीमों के साथ



2-2 मैच नहीं खेल पाती। जिस पर धूमल का मानना है कि व्यवस्था के कारण जगह इतनी नहीं है कि मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 की जाए।

डबल हेडर की संख्या बढ़ाना उन्हें व्यावहारिक नहीं लगता। हालांकि, उन्होंने माना कि भविष्य में आईपीएल विंडो को बढ़ाया जा सकता है। इसके पीछे का कारण उन्होंने लोगों की कुछ सीरीज में कम रुचि बताया।

दरअसल, धूमल ने कहा कि, पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि द्विपक्षीय सीरीज में लोगों की रुचि खत्म हो रही है। जिस कारण से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश अपनी खुद की टी20 लीग लेकर आए। उनके अनुसार, अगर ऐसा ही रहा तो हर देश सिर्फ उन्हीं द्विपक्षीय सीरीज पर ध्यान देगा जो आर्थिक रूप से उन्हें फायदा पहुंचाए। इस स्थिति में ही आईपीएल विंडो को बढ़ाया जा सकता है।

मास्टर्स राजस्थान राज्य टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का शुभारंभ आज से

जयपुर, 3 अप्रैल। राजस्थान वेटरन टेबल टेनिस समिति के तत्वावधान में आयोजित मास्टर्स राजस्थान राज्य टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2025 का शुभारंभ कल, दिनांक 04 अप्रैल 2026 से जयपुर में होगा।

यह प्रतियोगिता जयपुर जिला टेबल टेनिस संघ के सहयोग से राजस्थान टेबल टेनिस संघ के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 04 एवं 05 अप्रैल 2026 को वॉकर एकेडमी, वैशाली नगर में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेशभर के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे।

प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की विभिन्न आयु वर्ग श्रेणियों (40 वर्ष से 80 वर्ष तक), महिला वर्ग, पुरुष एवं महिला युगल तथा मिश्रित युगल मुकाबले खेले जाएंगे। साथ ही टीम चैम्पियनशिप भी आयोजित की जाएगी,

जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं, जिनमें कृष्ण मोहेश्वरी, सुकुंद अग्रवाल, सविता गुप्ता, राजेश आनंद एवं राजेश शर्मा शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की भागीदारी से प्रतियोगिता का स्तर और भी ऊंचा होने की संभावना है।

अजय ओझा (अध्यक्ष) एवं दीपांक दास (संयोजक) के अनुसार, यह चैम्पियनशिप प्रदेश के वेटरन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है तथा इससे टेबल टेनिस खेल को बढ़ावा मिलेगा। आयोजन समिति ने सभी खेल प्रेमियों एवं खिलाड़ियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें एवं इस खेल को महोत्सव का आनंद लें।

राजस्थान यूथ ने यूनिनयन क्रिकेट क्लब को हराया, मनस्वी कट्टा ने 4 विकेट लिए

जयपुर, 3 अप्रैल। जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित तथा एल वी फार्मा द्वारा प्रायोजित महिला ए डिवीजन लीग में आज खेले गए मैच में राजस्थान यूथ ने यूनिनयन क्रिकेट क्लब को 6 विकेट से हराया।

के एल सैनी स्टेडियम पर खेले मैच में यूनिनयन क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अनुष्का शर्मा के 14 रन, बिट्टू राजभर के 16 रन, तानिया के 12 रन, निधि सैनी के 21 रन व सीमा शर्मा के 11 रनों से 35.4 ओवर में 102 रन बनाकर आउट हो गईं। राजस्थान यूथ के लिए मनस्वी

कट्टा ने 9 पर 4, फ़ौरा गुर्जर ने 29 पर 4, प्रियांशी चौधरी ने 3 पर 2 व अंजलि ने 13 पर एक विकेट लिया। जवाबी पारी में राजस्थान यूथ ने नीतू शर्मा के 22 रन, कृतिका गुलाब के 12 रन, प्रियांशी चौधरी के 15 रन, रनेहा उबना के 19 रन, माहिरा खान के 14 रन नाबाद व अंजलि के 10 रन नाबाद से 21 ओवर में 6 विकेट पर 106 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया। यूनिनयन क्रिकेट क्लब के लिए निधि सैनी ने 15 पर 2, वेदी ने 32 पर 2, भूमि व सीमा शर्मा ने एक-एक विकेट लिया।

राजस्थान के रजत, जतिन, प्रखर, अभिषेक, हनी, नावेद बीसीसीआई अंडर 19 हाई परफॉर्मेंस कैम्प (सेंटर ऑफ़ एक्सीलेन्स) में चयनित

जयपुर, 3 अप्रैल। बीसीसीआई की राष्ट्रिय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के युवा प्रतिभावांन खिलाड़ी प्रखर शर्मा, रजत बघेल, जतिन सैनी, नावेद खान, अभिषेक, हनी प्रताप सिंह को बीसीसीआई की आल इंडिया जूनियर चयन कमेटी ने बीसीसीआई द्वारा राजकोट, नाडियाड, पाँडिचेरी में आयोजित होने वाले अंडर हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण शिविर (सेंटर ऑफ़ एक्सीलेन्स) में चयनित किया गया है।

प्रखर शर्मा, रजत बघेल व अभिषेक, राजकोट, जतिन सैनी, हनी प्रताप सिंह, नाडियाड, नावेद खान, पाँडिचेरी स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेन्स में आगामी



राजकोट, जतिन सैनी, हनी प्रताप सिंह, नाडियाड, नावेद खान, पाँडिचेरी स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेन्स में आगामी

कैंडलविक एकेडमी की जीत में फलक भुक्काल का शतक

जयपुर, 3 अप्रैल। राजस्थान यूथ क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय यूथ कप अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज खेले गए मैच में कैंडलविक एकेडमी ने के एल सैनी एकेडमी को 108 रनों से हराया। आर जे 14 ग्राउंड पर कैंडलविक एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फलक भुक्काल के 149 रन (107 गेंद, 22 चौके व 5 छक्के), हर्षित कुमार के 24 रन व देवांग दगांग के 81 रनों से 46.3 ओवर में 314 रन बनाए। के एल सैनी एकेडमी के लिए रमन चौधरी ने 71 पर 3, रोहित जांगिड़ ने 38 पर 3, गौरांश, यश भाला व लक्ष्यराज ने एक-एक विकेट लिया।



जवाबी पारी में के एल सैनी एकेडमी ने यशवर्धन प्रताप सिंह के 107 रन (99 गेंद, 12 चौके व 4 छक्के), रमन चौधरी के 47 रन, रुद्रांश सोनी के 14 रन से 37.1 ओवर में 206 रन बनाकर आउट हो गईं। कैंडलविक एकेडमी के लिए हिमांक झालानी ने 46 पर 4, फलक भुक्काल ने 31 पर 2, आयन कुमार ने 32 पर 2 शिवांग दगांग ने एक-एक विकेट लिया।

आपसी समन्वय से आयोजन को सफल बनायेंगे : नीतू बारूपाल

जेएस स्पोर्ट्स ने आईपीएल की तैयारियों का जायजा लिया

जयपुर, 3 अप्रैल। संयुक्त शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल तथा राजस्थान राज्य क्रोडा परिषद की सचिव नीतू बारूपाल ने शुक्रवार की शाम सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर में आगामी दिनों में होने वाले आईपीएल मैचों के लिए चल रही विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पीडब्ल्यूडी एवं क्रोडा परिषद के साथ राजस्थान रॉयल्स के अधिकारी/प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जयपुर में आईपीएल मैचों के लिए तैयारी प्रक्रिया माह से ही शुरू हो गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीम स्टेडियम में सभी तरह के नवीनीकरण एवं अपग्रेडेशन के कार्यों को समय पर पूरा कर स्टेडियम को मैचों के आयोजन के लिए तैयार कर देगी। आईपीएल मैचों के आयोजन से पहले



फ्लड लाइट्स, वीआईपी साउथ स्टेड्स के साथ नॉर्थ और अन्य स्टेड्स का सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कार्य पूरे किए जा रहे हैं। इस अवसर पर बारूपाल ने कहा कि सभी विभागों के बीच आपसी समन्वय से इस आयोजन को सफल

यति क्रिकेट अकादमी जीती

जयपुर, 3 अप्रैल। अंडर-12 पिकसिटी कप में यति क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 ओवर में 140 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए कविश अग्रवाल ने 22 और यशवर्धन ने 21 रनों का योगदान दिया। एस्आर पेस क्रिकेट अकादमी की ओर से ईशान सैनी ने 3, केशव और तनिष्क ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एस्आर पेस क्रिकेट अकादमी 33 ओवर में 73 रन पर आल आउट हो गई। यति क्रिकेट अकादमी 23 ओवर में 176.5 रन पर आल आउट हो गई। जय भारतीय क्रिकेट अकादमी ने 69 रन बनाकर मैच जीत लिया।

जल में 100 प्रतिशत घुलनशील उर्वरकों के लिए विक्रय और विपणन सूचना

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी आदेश संख्या एस.ओ. 2900 (ई) दिनांकित 24 अक्टूबर 2015 और इसके संशोधन दिनांकित 30 दिसम्बर 2017 के अनुसार। मैसर्स श्रीराम एगस्मार्ट लिमिटेड (डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की सहायक कम्पनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, (पश्चिमी विंग), वर्ल्ड मार्ग-1, एयरोसिटी, नई दिल्ली - 110037, भारत में स्थित है, एतद द्वारा सूचित करती है कि यह नीचे निर्दिष्ट अनुसार जल में 100 प्रतिशत घुलनशील उर्वरक ग्रेडों के मिश्रण बेचना चाहती है।

SI No.	Grades	NPKs									
		NPK 12-58-0	NPK 6-0-49	NPKs 00: 14:14:11	NPKs 15 -26-16-2	NPK 13 -10-27	NPK 13 -35-11	NPKs: 08: 35:15:0.2	NPKs13: 05:35:	NPK 11 -42-11	
1	Moisture per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Total Nitrogen per cent by weight, Minimum	12.0	6.0	0	15	13	13	8	13	12	
3	Water Soluble Phosphates (as P2O5) per cent by weight, Minimum	58.0	0.0	14	12	10	35	35	5	42	
4	Water Soluble Potash (as K2O) per cent by weight, Minimum	0.0	49.0	14	16	27	11	15	35	13	
5	Water Soluble Sulphur as Sulphate per cent by weight, Minimum			11	2						
6	Boron (as B) per cent by weight, Minimum							0.2			
7	Total Chloride per cent by Weight, Maximum	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
8	Matter Insoluble in water per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
9	Sodium (as NaCl) per cent by weight, Maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
10	Lead (as Pb) per cent by weight, Maximum	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
11	Cadmium (as Cd) per cent by weight, Maximum	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	
12	Arsenic (as As) per cent by weight, Maximum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

खुराक, प्रयोग के तरीके और लाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए कार्यालय से सम्पर्क करें। विपणन कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण: श्री राम एगस्मार्ट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 82, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा (भारत), सीआईएन नम्बर U24232DL2022PLC401518, उपभोक्ता सेवा नम्बर 0120-4040188, ईमेल: info@shriramagmart.com वेबसाइट: www.dcmshriram.com

उद्योगों को माल परिवहन व निर्यात के लिए जलमार्ग उपलब्ध करायेंगे- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जवाई-लूनी-रण ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग-48 की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए

जयपुर, 3 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को माल परिवहन एवं निर्यात के लिए जलमार्ग उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी क्रम में उन्होंने जवाई-लूनी-रण

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण एवं आईआईटी मद्रास को प्रोजेक्ट के तकनीकी व वित्तीय आंकलन तथा जहाजों के अनुमानित ट्रैफिक की तुलनात्मक व अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय जलमार्ग-48 को लेकर अहम बैठक की।

ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू)-48 को मूर्तरूप देने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय जलमार्ग-48 को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) एवं आईआईटी मद्रास को इस प्रोजेक्ट के तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं का आंकलन करने एवं जहाजों के अनुमानित ट्रैफिक की

तुलनात्मक एवं अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में 27 अक्टूबर 2025 को एनडब्ल्यू-48 के संबंध में राज्य सरकार ने आईडब्ल्यूएआई के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया, जिसके सम्बंध में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के. मुरली ने इस परियोजना के संबंध में डीपीआर की तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यह राष्ट्रीय जलमार्ग अस्तित्व में आएगा तो इससे प्रदेश के साथ ही

नजदीकी राज्यों के उद्योगों और व्यापारियों को भी सुगम माल ढुलाई का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय जलमार्ग प्रदेश के समग्र विकास का मजबूत आधार बन सकता है। साथ ही, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और माल ढुलाई की लागत में कमी लाने में उपयोगी साबित हो सकता है। प्रदेश में एनडब्ल्यू-48 के अस्तित्व में आने से रण ऑफ कच्छ के रास्ते अरब सागर तक माल की निर्बाध आवाजाही संभव हो पाएगी। राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरने वाला यह राष्ट्रीय

जलमार्ग पेट्रोकेमिकल्स, खनिजों, सीमेंट, केमिकल, औद्योगिक वस्तुओं सहित विभिन्न, निर्यात उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुनील पालीवाल, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित, संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

अमेरिका का एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इनम की घोषणा की गई है। यह विमान ईरान के मध्य हवाई क्षेत्र में गिराया गया, जिसे अमेरिका-इजरायल पूरी तरह अपने नियंत्रण में बनाते रहे हैं। युद्ध को और बढ़ाते हुए, ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की योजना की घोषणा की है। कुवैत, सऊदी अरब और बहरैन के महत्वपूर्ण सड़क पुलों को संभावित लक्ष्यों की सूची में शामिल किया गया है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि बुनियादी ढांचे की भारी नुकसान होना इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना सकता है। इससे तेल और गैस की आवाजाही प्रभावित होगी और निर्यात पर असर पड़ेगा। हालांकि, इसका सबसे बड़ा भार खाड़ी देशों की

आम जनता को उठाना पड़ेगा। शत्रुता कम होने के बजाय, ऐसा लगता है कि ईरान, अमेरिका की अवहेलना करते हुए अपने हमलों को और तेज कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता से इनकार किया है और अमेरिकी जमीनी कार्रवाई की स्थिति में कड़े जवाब की चेतावनी दी है, जैसा कि डॉनल्ड ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने एशिया के अन्य क्षेत्रों से 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात किया है। इसके अलावा, शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े को भी इस क्षेत्र में भेजने का आदेश दिया गया है, जिससे रणनीतिक रूप से पुनःतैनाती की जा रही है। अमेरिकी सैनिक पूर्व एशिया से पश्चिम एशिया की ओर तेजी से स्थानांतरित हो रहे हैं।

‘आम आदमी के मुद्दे उठाए तो आम आदमी पार्टी का क्या गया’

चंडीगढ़, 03 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाए जाने से आहत सांदरा राघव चड्ढा ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सवाल दगो है।

राघव चड्ढा ने आज सुबह एक वीडियो जारी किया। इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं, खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। मुझे जब-जब बोलने का मौका मिलता है तो मैं आम आदमी के मुद्दे उठाता हूँ। संसद में ऐसे मुद्दों पर बोलता हूँ जिन्हें आमतौर पर सदन में उठाया नहीं जाता।

उन्होंने स्वागत किया कि क्या जनता के मुद्दे उठाना, जनता के मुद्दों पर बात करना अपराध है। क्या मैंने कोई गुनाह

■ **आप नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने पर चुपची तोड़ी और कहा मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लें।**

कर दिया, कोई गलती कर दी? उन्होंने कहा मैं जब बात करता हूँ तो देश के आम आदमी की बात करता हूँ। संसद में एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, टोल व बैंक लूट का मुद्दा उठाया।

ट्रंप ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के बाद होर्मुज स्ट्रेट को बारूदी सुरंगों से मुक्त कराने में उनकी नौसैनिक क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी इसे संकेत दिए थे। अमेरिकी सहयोगी देशों में इस बात पर सहमति है कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को बलपूर्वक खोलना व्यावहारिक विकल्प नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि यह संकट ईरान के साथ समझौते के बिना हल नहीं हो सकता। गुजरात की बैठक में जापान ने फारस की खाड़ी में फंसे सभी जहाजों और उनके चालक दल के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग उपलब्ध कराने हेतु सहयोग का आ आ किया। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने, एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा अधिकतम प्रयास करने के महत्व पर जोर दिया।

बैठक में यह चिंता भी व्यक्त की गई कि ईरान होर्मुज में टोल व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहा है। वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों ने जलमार्गों में लगभग पूरी आवाजाही रोक दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग बंद हो गया है और पेट्रोलियम की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं।

भारत आ रहा ईरानी तेल टैंकर गुजरात के पास आकर चीन की तरफ मुड़ गया

बताया जा रहा है कि तेल के पेमेंट को लेकर कुछ समस्या आ गई है

नई दिल्ली, 03 अप्रैल। भारत के लिए आ रहा ईरानी कच्चे तेल का टैंकर अचानक अपना रास्ता बदलकर चीन की ओर मुड़ गया। यह टैंकर करीब 7 साल बाद भारत पहुंचने वाला पहला ईरानी तेल जहाज था और गुजरात के वाडिनार पोर्ट की ओर आ रहा था। इसमें करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ था। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जहाज पिछले तीन दिनों से भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन गुजरात के पास पहुंचने से ठीक पहले उसने अपना रास्ता बदल दिया और अब चीन के डोंगयिंग शहर की तरफ जा

■ **पिंग शुन नामक यह टैंकर अब चीन के डोंगयिंग शहर की तरफ जा रहा है।**

रहा है। बाजार सूत्रों के हवाले से उन्होंने कहा कि जहाज के रास्ता बदलने का मुख्य कारण ईरानी कच्चे तेल की खरीद में पेमेंट शर्तों में बदलाव है। पहले डिक्रेता 30 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि देते थे, लेकिन अब वे एडवॉन्स पेमेंट की मांग कर रहे हैं। पेमेंट मिलने के बाद ही तेल की खेप खाना करने की बात

हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरानी तेल के व्यापार में बीच रास्ते में गंतव्य बदलना पूरी तरह नया नहीं है, लेकिन यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार में वित्तीय शर्तों और कार्टेलरपार्टी रिस्क बेहद संवेदनशील हो गए हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कार्गो को किस भारतीय रिफाइनरी में खरीदा था। गुजरात के वाडिनार बंदरगाह के जरिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नायर एनर्जी और भारत महेंद्र कर्मा सहित, 30 कोरेस नेटवर्क जैसी कई बड़ी रिफाइनरियां कच्चा तेल आयात करती हैं।

‘संसद का तीन दिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जनगणना के आंकड़े 2027 तक उपलब्ध हो सकते हैं। रमेश ने कहा कि रिजिजु ने अपने पत्रों में केवल महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठाया, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेष सत्र में देशभर में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर भी चर्चा हो सकती है।

उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार को ओर से परिसीमन का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, लेकिन पार्टी ने अनौपचारिक रूप से यह सुना है कि संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन का प्रस्ताव है। कहा जा रहा है कि सरकार संसदीय और विधानसभा सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि दक्षिणी राज्य, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उत्तर-पश्चिमी राज्य पंजाब को सीटों की संख्या के मामले में गंभीर नुकसान होगा। जयभार रमेश ने कहा कि हालांकि

सरकार का प्रस्ताव 50 प्रतिशत सीट बढ़ाने का है पर वास्तव में सीटों में काफी वृद्धि होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में संसदीय सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी, जबकि केरल में सीटें 20 से बढ़कर 30 हो जाएंगी। पहले 60 सीटों का अंतर था, अब 90 हो जाएगा। उन्होंने कहा, “अगर परिसीमन भी प्रस्तावित है, तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और इसे बलपूर्वक नहीं करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के सांसदों और फिर विपक्षी दलों के साथ बैठक करेंगे, ताकि संयुक्त रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया, पूरा विपक्ष एकजुट है और भाजपा का ‘फूट डालो और राज करो’ का प्रयास सफल नहीं होगा। रमेश ने दोहराया कि विशेष सत्र का एकमात्र उद्देश्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित कर लाना उठाना है। उन्होंने कहा, “यह एक चुनौती सत्र है।”

सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) में करीब 7.7 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं साल 2021 की भर्ती प्रक्रिया के कई अभ्यर्थियों ने वर्तमान परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं किया है। ऐसे में इन्हें अनुमति देने से पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। वहीं हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे 713 अभ्यर्थियों को पहले की परीक्षा में शामिल कर उनके प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह परीक्षा 41 शहरों के 1173 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। ऐसे में इतने बड़े स्तर अंतिम समय में इतने अतिरिक्त अभ्यर्थियों को समायोजित करना गंभीर चुनौती पैदा करेगा।

गौरतलब है कि एक दिन पहले हाईकोर्ट ने ओवरएज हो चुके याचिकाकर्ता और उस जैसे अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश देते हुए परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया था।

प.बंगाल में भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पर्यटकों का स्वागत करता है। हमारे व्यंजनों को मिस न करें। राजनीतिक विश्लेषक मैदुल इस्लाम ने कहा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल को “मूल रूप से एक बंगाली परियोजना” के रूप में देखती है। उन्होंने कहा, “उस बंगाली परियोजना में, मछली खाना एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब अन्य जगहों पर मछली बाजारों पर हमला होता है, या हिंदी भाषी नेता मछली पर नाक-भौं सिकोड़ते हैं, तो यह चुनावी मुद्दा बन जाता है। टीएमसी कह रही है कि वह बंगालियों को ऑर्गेनिक पार्टी है और इसलिए बंगाली भोजन की आदतों से ऑर्गेनिक रूप से जुड़ी है।” यह तर्क इसलिए प्रभावकारी हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मछली के साथ रिश्ता केवल भोजन तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में, मछली जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण का हिस्सा है, नवजात के चावल खाने की सबसे

रामगढ़ में जंगली हाथियों ने तीन को कुचल कर मारा

रामगढ़, 03 अप्रैल। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार को जंगली हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाते हुए तीन ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) नीतीश कुमार के अनुसार, हाथियों का झुंड सबसे पहले बंदा गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर पहुंचा, जहां काम

■ **हाथियों के हमले में कई अन्य घायल हो गए हैं। वन विभाग ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है साथ ही विभाग घायलों का इलाज भी करवा रहा है।**

कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। दो मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद हाथियों का झुंड पुरपा गांव की ओर बढ़ गया, जहां महोआ चुन रहे 74 वर्षीय श्यामदेव साहू को भी हाथियों ने कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, सुती धोड़घोड़िया बस्ती में महोआ चुन रही एक महिला पर भी हाथी ने हमला कर दिया।

जोधपुर में मकान की छत पर चल रही एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी

एंटी गैंगस्टर टॉस्क फोर्स ने 3 करोड़ रूपए के एमडी ड्रग्स कैमिकल जब्त किए

जोधपुर, 3 अप्रैल (कास)। जोधपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने एक मकान की छत पर चल रही एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है। एजीटीएफ ने मौके से 3.055 किलोग्राम एमडी ड्रग्स और 55 किलो

725 ग्राम घातक रसायन बरामद किए हैं। जब की गई ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत तीन करोड़ रूपए आंकी गई है, साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एजीटीएफ ने मंडली बालोतरा, हाल निवासी शंकर नगर, बनाडू निवासी गणपतराम बेनीवाल को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही एजीटीएफ ने राजस्थान के निर्देशन में की गई।

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने 12 लाख का कर्ज चुकाने के लिए सांचौर के तस्कर आसुराम उर्फ लक्की और भानु के साथ सौदा किया था। इसके लिए उसने अपने ही घर बेनीवाल सदन, को ड्रग बनाने की लैब में तब्दील कर लिया था। जानकारी के अनुसार, मौके से बरामद खतरनाक रसायनों से 60 किलो एमडी ड्रग्स तैयार करने की योजना थी।

■ **आरोपी गणपत राय बेनीवाल ने सांचौर के दो तस्करों के साथ सौदा करके अपने घर को लैब में परिवर्तित कर लिया था। उसकी 60 किलो एमडी ड्रग्स बनाने की योजना थी।**

एजीटीएफ ने बताया कि राजस्थान एजीटीएफ को लगातार सूचना मिल रही थी कि जोधपुर शहर में माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में ड्रग्स पैडलरों को एमडी ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। इसी क्रम में एजीटीएफ के एएसआई राकेश जाखड़ को मिली गोपनीय सूचना पर एएसपी ज्ञानचंद यादव और एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के सुपरविजन में एक विशेष टीम गठित की गई। एजीटीएफ, एटीएस, डीएस्टी और बनाडू थाना पुलिस ने रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में बने मकान की घेराबंदी की। जब टीम मकान की छत पर पहुंची तो वहां का नजारा देख हैरान रह गई। बिजली के बल्ब की रोशनी में गढ़ पर एमडी ड्रग्स सुखाई जा रही थी। वहां रसायनों के ड्रम व इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे बिखरे पड़े थे। मौके से 3.055

किलोग्राम निर्मित एमडी ड्रग्स, डाइक्लोरोमीथेन, मैक्स फाइन केम, डी-आयोनाइज्ड वॉटर और ज्योति हाईड्रोटेक जैसे घातक कैमिकल और इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, 9 बाल्टियां, स्टील के बर्तन और ड्रग्स सुखाने के उपकरण जब्त किए गए।

इस ऑपरेशन में एएसआई राकेश जाखड़ और कांस्टेबल सुमेर सिंह की विशेष भूमिका रही। तकनीकी सहयोग एएसआई रमेश कुमार यादव ने दिया। वहीं बनाडू थानाधिकारी लेखराज और डीएस्टी प्रभारी खेत सिंह की टीम ने मौके पर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले की तपतीश अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमृत लाल जीनगर को सौंपी गई है। पुलिस अब मुख्य सराना आसुराम उर्फ लक्की और भानु की तलाश में दबिश दे रही है।

बिहार में जहरीली शराब कांड में 5 की मौत, 15 गंभीर

मोतिहारी में हुए इस हादसे में कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है

मोतिहारी, 03 अप्रैल। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने भयावह रूप ले लिया है। अब तक इस घटना में पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। सभी घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कई पीड़ितों की हालत चिंताजनक बनी हुई है और कुछ ने आंखों की रोशनी तक खो दी है।

इस मामले में बड़ा खुलासा यह है कि शुरुआत में पुलिस प्रशासन इस घटना को शराब कांड मानने से इनकार कर रहा था। हालांकि लगातार बढ़ते मामलों और मौतों के बाद अब दबी जुबान में जहरीली शराब से मौत की बात स्वीकार की गई है। पहले जहां छह लोगों के बीमार होने की बात कही गई थी, वहीं अब आंकड़ा 15 के पर पहुंच चुका है।

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नागा राय को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा, मार्च महीने में छपरा जिले में भी जहरीली शराब से बड़ा हादसा हुआ था फिर भी प्रशासन नहीं चेता। एक अन्य आरोपी जम्मू बैठा को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस का दावा है कि इस अवैध शराब नेटवर्क को तोड़ने के लिए सफलता मिली है और पूरे गिरोह की पहचान की जा रही है।

■ **मार्च महीने में छपरा जिले में भी जहरीली शराब से बड़ा हादसा हुआ था फिर भी प्रशासन नहीं चेता।**

एक अन्य आरोपी जम्मू बैठा को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस का दावा है कि इस अवैध शराब नेटवर्क को तोड़ने के लिए सफलता मिली है और पूरे गिरोह की पहचान की जा रही है।

इस कांड में लापरवाही सामने आने के बाद परसोना के चौकीदार भरत राय को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं तुरकौलिया थाना के एसएचओ उमाकांत माझी को भी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरकौलिया और रघुनाथपुर थानों में

हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक प्रमोद यादव और हीरालाल भगत के परिजनों के आवेदन पर केस दर्ज किया गया। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है।

पुलिस का कहना है कि जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल कच्चे माल की खरीदारी के स्रोतों का भी पता लगाया जा रहा है। छापेमारी लगातार जारी है

मालदा कांड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एजीटी नॉर्थ बंगाल के जयप्रमन ने कहा कि हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे कि यह पहले से प्लान किया गया था या नहीं। इस घटना के बाद हमने न्यायिक अधिकारियों को भी एसपीएफ सुरक्षा दी है।

इस घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 को ब्लॉक किया,

और कई संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस का दावा है कि इस अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले मार्च महीने में छपरा के मशरक और पानापुर में भी जहरीली शराब से चार लोगों की मौत हुई थी। बावजूद इसके, अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है।

मालदा कांड का ...

पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की। हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मोफक्करल इस्लाम का जुड़ाव एआईएमआईएम से बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा हिंसा को इसे एक सोची-समझी साजिश बताया और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया।

कुख्यात माओवादी प्रशांत बोस की जेल में मौत

रांची, 03 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की साजिश रचने और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की हत्या में अहम भूमिका निभाने वाले भाकपा (माओवादी) का शीर्ष सदस्य एवं 1 करोड़ के इनामी रहे प्रशांत बोस की लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को रांची के बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार में मौत हो गई। जेल मानिरीक्षक (आईजी) सुदर्शन मंडल ने प्रशांत बोस उर्फ किशन दा के मौत की पुष्टि की है। प्रशांत बोस की भूमिका पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की साजिश रचने में थी।

एनआएपी की चार्जशीट में भी बोस का नाम सामने आया है। वहीं, छत्तीसगढ़ में साल 2013 में बस्तर संभाग के झीरम घाटी में सलवा जुद्धम के खिलाफ विचारणप शुक्ल, नंदकिशोर पटेल, दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा सहित, 30 कोरेस नेटवर्क की हत्या की वारदात को अंजाम देने की मंजूरी प्रशांत बोस ने ही दी थी।

अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया

अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस बारे में जानकारी दी

वाशिंगटन, 03 अप्रैल। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ईरान से छिड़े युद्ध के बीच देश के सेना प्रमुख (आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ) जनरल रैंडी जॉर्ज से पद छोड़ने और तुरंत रिटायरमेंट लेने को कहा है। हेगसेथ के मुख्य प्रवक्ता शॉन पॉर्नेल ने कहा, “जॉर्ज आर्मी के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से तुरंत प्रभाव से रिटायर हो रहे हैं। युद्ध विभाग जनरल जॉर्ज की दशकों की सेवा के लिए उनका आभारी है। हम उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।”

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सेना प्रमुख के साथ आर्मी के दो अन्य अधिकारियों, जनरल डेविड होडने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी उनके पदों से हटा दिया गया है। होडने आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग

■ **सीबीएस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार इसी के साथ जनरल डेविड होडने और मेजर जनरल विलियम को भी हटा दिया गया।**

कमांड का नेतृत्व कर रहे थे। ग्रीन, आर्मी के चैपलैन को भी प्रमुख थे। आर्मी ऑफ स्टाफ जॉर्ज ने इससे पहले 2021 से 2022 तक (बाइडेन प्रशासन के दौरान) रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के वरिष्ठ सैन्य सहायक के रूप में कार्य किया था। पेरोव इन्स्ट्रुटी अधिकारी और वेस्ट पॉइंट से स्नातक जॉर्ज ने सबसे पहले पहले खाड़ी युद्ध में और उसके बाद

हाल ही में हुए इराक और अफगानिस्तान के संघर्ष में सेवा दी।

हेगसेथ ने और भी कई अधिकारियों को हटाया है। इन्हें जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल सीन्यू ब्राउन, नेवल ऑपरेशंस के चीफ एडमिरल लिंसा फ्रॉन्टो, एयर फ़ोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स स्लाइफ और डिफेंस इंटील्लिजेंस एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफ्री क्रूस शामिल हैं। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का कार्यकाल आमतौर पर चार साल का होता है। जॉर्ज को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पद के लिए नामित किया था और 2023 में सीनेट ने उनकी नियुक्ति की थी। इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में वे 2027 तक इस पद पर बने रहते।

तारागिरी युद्धपोत नौसेना में शामिल

नई दिल्ली, 03 अप्रैल। भारतीय नौसेना में शुक्रवार को एक नवीनतम स्टील्थ युद्धपोत, ‘तारागिरी’ शामिल किया गया है। इस युद्धपोत को विशाखापत्तनम में 3 अप्रैल को दोपहर नौसेना में कमीशन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। ‘तारागिरी’ नामक यह युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती है। इसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में चलने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली भी है। अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली व घातक हथियारों से लैस यह युद्धपोत दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘तारागिरी’ को एक स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप करार दिया।

उन्होंने कहा कि तारागिरी की कमीशनिंग, भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक शक्ति का प्रतीक है।

‘नेशनल और स्टेट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) वह अतिक्रमण घटाने की कार्रवाई जल्दी करे, इसके लिए जल्द से जल्द नोटिस जारी किए जाएं। हालांकि प्रभावितों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडुी ने सिरसी रोड पर खालीपुरा तिराहे से झाड़खंड मोड़ तक अतिक्रमण घटाने को लेकर 6 सप्ताह का समय मांगा है। इस पर अदालत ने जेडीए को समय देते हुए सिरसी रोड के अतिरिक्त, जयपुर शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों व हाईवे से भी अतिक्रमण घटाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खालीपुरा मोड़ से लेकर झाड़खंड मोड़ तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए 5 मार्च को दिए थे, क्योंकि उस समय जेडीए प्रशासन ने मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए सक्षम नहीं था। कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र पेश करते

हुए जेडीए की ओर से कहा गया है कि सिरसी रोड पर सी ज़ोन बायपास से पांचवाला तक 160 फीट रोड है, लेकिन करीब डेढ़ किलोमीटर दूरी में 95 से ज्यादा दुकान-मकान सड़क सीमा में हैं। इसके साथ ही, मौनावाला से सिरसी मोड़ तक भी 96 मकान, दुकान और अन्य स्ट्रक्चर सड़क सीमा में बनाए हुए हैं। यह तथ्य जेडीए को अर.एन. ज़ोन और ज़ोन-7 के द्वारा करवाए गए पी.टी. सर्वे में सामने आया है। इन अतिक्रमणों को घटाने के लिए प्रवर्तन शाखा नोटिस जारी करेगी।

माल्दा में जजों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, बुधवार की घटना की जांच का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनआरएपी टीम शुक्रवार को मालदा पहुंचेगी और जांच शुरू करेगी।